bjpkamaljyoti@gmail.com / www.up.bjp.org

संवत 2078 युगाब्द 5123 कुल पृष्ठ – 50 अंक – 13

वर्तमान कमल ज्योति

संकल्प से सिद्धि

सोंच ईमानदार, काम असरदार

विशेषांक

₹10

कार्यकर्ता सम्मेलन
दमदार
यूपी फिर मांगे

नामांकन
विजय

सुराज की विचार यात्रा
वर्तमान कमल ज्योति

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री स्वतंत्र देव सिंह
सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी
प्रबन्ध सम्पादक
राजकुमार
प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

पूज्य संत रामानुजाचार्य जी

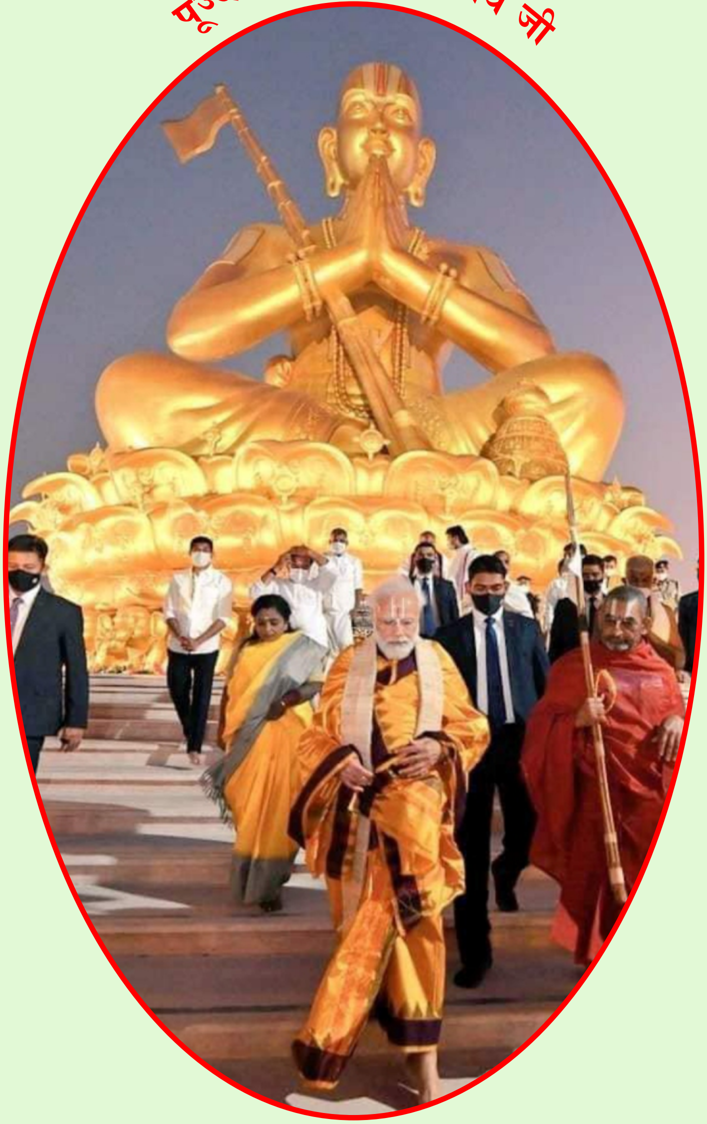

कोटिशः नमन!

''स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी''

सम्पादकीय

शुभ संकल्प, विकास का मूल मंत्र

देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार यानी ''**मोदी योगी**'' के दृढ़ संकल्पो के साथ चलने वाला शासन–प्रशासन, जिसके केन्द बिन्दु में भारत माता की जय की गूँज है। आम जन के कल्याण का पवित्र संकल्प है, आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष, वैश्विक आपदा करोना से जुझ रहा पूरा विश्व ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास, सांस्कृतिक उत्थान भारत का निरन्तर सुदृढ़ होना ''**संकल्प से सिद्धि**'' का मूल महामंत्र है। पाँच प्रदेशों में चुनाव हो रहे हें। विरोधियों के निशाने पर भाजपा के नेता–नीति–नियति है। भारत देश वैश्विक क्षितिज पर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है।
देश का 2022–23 का बजट जब वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने रखा तो उस पर ''**चुनावी लालच**'' की कहीं परछाई तक नहीं दिखी, दिखा तो समृद्ध राष्ट्र के आमजन के सर्वांगीण विकास, गरीब कल्याण, सुरक्षा का पुनीत संकल्प, विकासशील से विकसित राष्ट्र का सद्मार्ग, सही दिशा, ईमानदार सोंच, असरदार काम जिसके कारण पूरी दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व की सराहना हो रही है।
उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी स्पष्ट नीति, सुशासन, अन्त्योदय, गरीब कल्याण, संतुलित विकास, सांस्कृतिक विरासत पुनरुत्थान के मूल संकल्पों के साथ 2022 के चुनाव का लोक कल्याण संकल्प पत्र मा0 अमित शाह जी ने जारी किया।
अपने पाँच वर्षों के शासनकाल में योगी सरकार ने जिस प्रकार से आपदाकाल में सेवा, विकास, सुशासन से प्रदेश को समृद्ध बनाया वह अतुलनीय है।
आज उत्तर प्रदेश गुण्डाराज से मुक्त, भ्रष्टाचार, अराजकता को तिलांजलि दे प्रगति के पथ पर बढ़ चला है। देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश की गणना होने लगी है। प्रत्येक जिले में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, विद्युत व्यवस्था सुधर रही है। सांस्कृतिक आस्था केन्द्रों के विकास से पुनः उत्तर प्रदेश देवभूमि के रूप में पुर्नस्थापित हो रहा है। श्रीराम मन्दिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, माँ विन्ध्यवासिनी धाम का विकास, मथुरा की निखरती आभा के साथ सड़कों का बिछता जाल, एक्सप्रेस हाइवे की बढ़ती संख्या, मेट्रो सेवा, एयरपोर्ट का विकास, पेयजल की हर घर में पहुंच। गरीबों को अन्न, मकान, गैस, चिकित्सा सुविधा आमजन के जीवन स्तर को संवारने, सुधारने में लगी है। कथनी–करनी में अन्तर न होना इस सरकार की विशेषता रही है। सबका साथ, सबका विकास इसका मूल संकल्प रहा है। ''**अन्तिम व्यक्ति**'' इसकी प्राथमिकता में है। एक राष्ट्र, श्रेष्ठराष्ट्र भाजपा की साधना रही है। ऐसे में लोकलुभावन, खोखला वादा, वचन नहीं। ये पूर्वजों का स्मरण कर पवित्र संकल्प है जिसके लिए भाजपा ''**मोदी योगी**'' सरकार प्रतिबद्ध है आइये इन संकल्पों की पूर्णता हेतु अपनी आहुति राष्ट्र समाजहित में अर्पित करें।

akatri.t@gmail.com

लोक कल्याण संकल्प "सबका साथ, सबका विकास"

साधक राजकुमार

प्रदेश के चुनावी महासमर में भाजपा की संकल्प पत्र प्रदेश वासियों के विश्वास, आशा का शुभ संकल्प हो गया है। बहु प्रतिक्षित वादों की सूची लोभ, लालच, झूठे आश्वासनों से अलग प्रदेश का सर्वोत्तम बनाने का संकल्प दोहरा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया। इंन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान के सभागार में जन आकांक्षा के अनुरूप जन–आशा–विश्वास पर आधारित लोक कल्याण संकल्प पत्र है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्रदेव सिंह, प्रदेश सहप्रभारी श्री अनुराग ठाकुर, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री दिनेश शर्मा और भाजपा की लोक कल्याण संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष एवं प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित थे। श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार 300 से अधिक सीटों पर जीत के साथ विजय की भव्य कहानी लिखने जा रही है।

हम बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गाँवों का समग्र विकास करेंगे। हम हर बेघर को घर उपलब्ध करायेंगे।

पांच वर्ष पूर्व हमने उत्तर प्रदेश का संकल्प पत्र जारी किया था। ये महज हमारा घोषणापत्र नहीं था बल्कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित करने का, प्रदेश के भविष्य को संवारने का और यूपी को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प था। मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता का आभारी हूँ कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारे संकल्प पत्र को स्वीकार किया और हमें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। विगत पांच वर्षों से श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिस्थापित करने का महती कार्य किया है। 2017 से पहले सपा और बसपा के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण और प्रशासन का संपूर्ण राजनीतिकरण हो गया था। पांच वर्षों की भाजपा सरकार के बाद मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपराधीकरण से और प्रशासन को राजनीतिकरण से मुक्ति दिलाई है। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कुछ दिन

पहले सपा के अध्यक्ष ने हमारे घोषणापत्र को लहराते हुए कहा था कि भाजपा बताये कि इसमें कितनी घोषणाएं पूरी हुई। मैं आज उत्तर प्रदेश की महान जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2017 के हमारे संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार ने विगत पांच वर्षों में इसमें से 92% संकल्पों को पूरा किया है। यह हमारी कार्यसंस्कृति है कि हम जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। इसी कारण देश के हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बारंबार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करती है। मुझे विश्वास है कि इस बार भी हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र को उत्तर प्रदेश की महान जनता पूरे मनोयोग से स्वीकार करेगी, योगी आदित्यनाथ सरकार पर विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः 300 से अधिक सीटों पर जीत दिलाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार का गठन करेगी।

मा0 मोदी जी के नेतृत्व में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अर्थव्यवस्था, गरीब–कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर – हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के संकल्पों को पूरा किया। देश के लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के लगभग 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का लगभग 36,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ़ किया। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए लगभग 4.72 लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया। साथ ही, विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सभी लंबित 17 परियोजनाओं को पूरा किया। इनमें से तो कुछ परियोजनायें ऐसी है जो मेरे जन्म से भी पहले की थी। इस बार के बजट में केन–बेतवा लिंक परियोजना के लिए अलग से आवंटन किया गया है।

"योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपराधीकरण और प्रशासन को राजनीतिकरण से मुक्ति दिलाया"

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश पहले एक दंगा मुक्त प्रदेश माना जाता था और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में थी। भाजपा की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। विगत पांच वर्षों में पिछली सपा सरकार की तुलना में डकैती में लगभग 57%, लूट में 70%, हत्या में 30%, अपहरण में 52% और बलात्कार में भी लगभग 42% की कमी दर्ज की गई है। साथ ही, दहेज़ के कारण होने वाली महिलाओं की मृत्यु में भी कमी आई है। मैं इसके लिए श्री योगी जी को साधुवाद देता हूँ।

उत्तर प्रदेश में एंटी भू–माफिया टास्क फ़ोर्स का गठन किया। इसके तहत पिछले पांच वर्षों में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति को भू–माफियाओं से मुक्त कराया। अब उस जगह पर गरीबों के आवास बन रहे हैं, शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। हमने ग्रेड तीन और ग्रेड चार की भर्ती से इंटरव्यू खत्म कर भ्रष्टाचार को खत्म किया। हमारे सरकार ने पुलिस हेल्पलाइन का विस्तार किया है।

पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में 25 से अधिक मेडिकल कॉलेज खुले। आज उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में से हर जनपद में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, 51 नए महाविद्यालय खुले हैं, महाविद्यालयों के लिए 79 भवनों का निर्माण किया गया है तथा 30 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। विगत पांच वर्षों में यूपी में मेडिकल सीटों की संख्या 1,900 से बढ़ कर 4,200 हुई है। विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में 28 नए इंजीनियरिंग कॉलेज, 26 पोलिटेक्निक कॉलेज और 771 कस्तूरबा गाँधी स्कूल खोले गए हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने काफी सराहनीय कार्य किया है। अखिलेश यादव ने मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। वो तो अच्छा है कि यूपी की जनता अखिलेश यादव की बात को मानती ही नहीं। यदि गलती से भी जनता ने बात मान ली होती तो तीसरी लहर में क्या हम सुरक्षित रह पाते? सबसे ज्यादा कोविड टीका भी उत्तर प्रदेश में ही लगा। पांच साल पहले उत्तर प्रदेश का हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल था लेकिन आज उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्ष में लगभग 1.80 लाख कोविड बेड्स बने, 541 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें से 200 ऑक्सीजन प्लांट्स बन कर तैयार हो गए हैं। 12वीं तक के छात्रों को बैग, किताब, जूते और स्कूल यूनिफॉर्म मुफ्त प्रदान किये गए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में भारत की महान संस्कृति के सभी आस्था केन्द्रों का विकास हुआ है। अयोध्या में भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ

और माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में में देश भर में जारी गरीब कल्याण मिशन की हर योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को हुआ है। गरीबों के घर बने हैं और हर घर में गैस, बिजली, पानी और शौचालय का प्रबंध किया गया है। साथ ही, हर गरीब को आयुष्मान कार्ड का कवच भी दिया गया है।

लोक कल्याण संकल्प पत्र समिति ने तकरीबन दो करोड़ सुझावों का अध्ययन किया और इसके आधार पर हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र बन कर तैयार हुआ है।

समृद्ध कृषि

अगले 5 वर्षों में हम सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। हम ₹5,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल तालाब एवं टैंक निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करेंगे। हम ₹25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री–इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर प्रदेश भर में छँटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चेम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण करेंगे। हम ₹1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे। हम ₹5,000 करोड़ की लागत के साथ गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करेंगे। साथ ही, स्थानीय मांग के अनुसार प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करेंगे। हम अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं एवं धान की खरीद को और मजबूत करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान प्राप्त हो. और देरी से होने वाले भुगतान के लिए मिलों से व्याज वसूल करके गन्ना किसानों को व्याज समेत भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करेंगे। प्रदेश में निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत मछुआरों को 1 लाख तक की नाव 40% सब्सिडी पर उपलब्ध कराएंगे। हम मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25% तक की सब्सिडी प्रदान करेंगे एवं 6 मॉडल मत्स्य मंडी स्थापित करेंगे।

सशक्त नारी–आत्म निर्भर समाज

उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने पर हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को ₹15 हजार से बढ़ाकर ₹25 हजार तक करेंगे। हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों के विवाद हेतु 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली तथा दीपावली पर 2 मुफ्त एल.पी.जी. सिलेंडर प्रदान करेंगे। हम 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करेंगे। हम 1,000 करोड़ की लागत के साथ मिशन पिंक टॉयलेट शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण एवं रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। हम विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करेंगे। हम 3 नई महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार कर उसे दोगुना करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और भी सुनिश्चित करेंगे। हम सभी सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों के पास सी.सी. टी.वी. कैमरे लगवाएंगे एवं 3,000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित करेंगे। हम ₹5,000 करोड़ की लागत के साथ

अवंती बाई लोधी स्वयं सहायता समूह (SHG) मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत 5 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाई जाएगी। हम स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली लगभग 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एस.एच.जी. क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ₹1लाख तक का ऋण न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराएगे। हम लोक सेवा आयोग (UPPSC) सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना करेंगे। हम कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रानी लक्ष्मी बाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी वितरित करेंगे।

सबको सुगम शिक्षा

उत्तर प्रदेश में पुनः योगी आदित्यनाथ सरकार बनने पर हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे तथा उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करेंगे। हम माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 30,000 माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। हम हायर एजुकेशन रेनोवेशन मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के कॉलेजों (आईटीआई एवं पॉलीटेक्निक समेत) के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो। हम अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालयों के निर्माण को पूरा करेंगे। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में डॉ राजेन्द्र प्रसाद नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोटर्स विश्वविद्यालय और लखनऊ एवं नोएडा में डिजिटल अध्ययन अकादमी की स्थापना की जायेगी। हम ₹2,500 करोड़ की लागत के साथ विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक ब्लॉक में एक आई.टी.आई. की स्थापना करेंगे।

स्वस्थ सक्षम युवा

पिछले पांच वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। हम हर परिवार में कम से कम एक –रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इच्छुक युवाओं को अभ्युदय योजना के अंतर्गत यू.पी.एस.सी. यू.पी.पी.एस.सी. एन.डी.ए. सी.डी.एस. जेईई, एन.आई.आई.टी., टी.ई.टी. क्लैट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ टैब्लेट अथवा स्मार्टफोन वितरित करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरु करेंगे जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों समेत पूरे प्रदेश में खेल हफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण करेंगे। सभी सरकारी खेल प्रशिक्षण अकादमियों में प्रशिक्षित प्रत्येक खिलाड़ी को मुफ्त स्पोट्र्स किट एवं उपकरण वितरित करेंगे। स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे।

सबको चिकित्सा स्वस्थ प्रदेश

उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने पर हम प्रदेश के हर जिले में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम लगभग ₹30,000 करोड़ के निवेश के साथ 6 धन्वंतरि मेगा हेल्थ पार्क स्थापित करेंगे, जिनके अंतर्गत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य एवं सर्जिकल उपकरणों और दवाओं जैसी चिकित्सीय सुविधाओं के उत्पादन का विस्तार कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगे। हम ₹10,000 करोड़ की लागत के साथ महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रदेश में हर स्तर पर सुचारु स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण करेंगे। हम मिशन जीरो की शुरुआत करेंगे जिसके अंतर्गत डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, जीका वायरस, जापानी एन्सेफलाइटिस एवं कालाजार जैसी वेक्टर बोर्न बीमारियों को मिटाने की पहल करेंगे। हम अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस एम्बुलेंस की संख्या को दोगुना करेंगे। हम प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र स्थापित कर किडनी रोगियों को लाभ पहुंचाएंगे। हम प्रदेश में एम.बी.बी.एस. जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या को दोगुना करेंगे। हम 6,000 डॉक्टरों एवं 10,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र करेंगे। हम प्रदेश में जन औषधि केंद्र के नेटवर्क का विस्तार कर सभी नागरिकों को कम कीमत में ज़रूरी दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश को टी–बी मुक्त बनाएंगे।

सुशासन से सुराज

एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर गुंडे, अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्यवाही इसी बढ़ता से आगे भी जारी रखेंगे। हम प्रदेश के सभी नागरिकों को 339 सरकारी सेवाएं निश्चित अवधि प्रदान कर रहे हैं। इसमें और वृद्धि करेंगे। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक

पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे। लव जिहाद करने पर कम से कम 10 वर्षों की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे। आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर एवं बहराइच में एंटी–टेररिस्ट कमांडो सेंटरों का निर्माण करेंगे। हम प्रदेश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक साइबर हेल्प डेस्क (सी.एच.डी.) स्थापित करेंगे।

अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास, आत्म निर्भर प्रदेश

उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उत्तर प्रदेश में लगभग ₹10 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करेंगे। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेकिंग में उत्तर प्रदेशको नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरु करके सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्री एवं डेफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण करेंगे। हमने पिछले 5 वर्षों में एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू करके हर जिले के एक उत्पाद को पहचान दी एवं 25 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए है। अगले 5 वर्षों में निर्यात एवं रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसरों को दोगुना करेंगे। हम बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करेंगे। हम प्रदेश में 5 विश्व स्तरीय एक्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर स्थापित करेंगे। हम सभी एक्सप्रेस–वे के निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करेंगे जिससे 5 लाख युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे। इसके अंतर्गत हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज प्लाट, रसायन, दवा एवं मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग आदि को बढ़ावा देंगे। हम प्रदेश में 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क स्थापित करेंगे। हम आत्मनिर्भर युवा स्टार्ट–अप मिशन बनाकर 10 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और हम स्टार्ट–अप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम तीन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करके 4 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हम कानपुर में मेगा लेदर पार्क स्थापित करके 2 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हम अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टैक्सटाइल हब बनाकर 5 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए 6 औद्योगिक पार्कों के निर्माण को पूरा करेंगे जहाँ लाखों युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हम संभाग स्तर पर आईटी पार्क की स्थापना कर लाखों रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

आधारभूत संरचना – समग्र ग्रामीण का विकास

उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार के पुनः बनने पर हम बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गाँवों का समग्र विकास करेंगे। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ेंगे, गाँवों में पक्के ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था बनाकर जल निकासी की समस्या को दूर करेंगे। 2024 तक हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस–वे नेटवर्क का रिकॉर्ड समय में निर्माण पूर्ण करेंगे। हम काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज मेट्रो परियोजनाओं पर काम करेंगे। हम अयोध्या इंटरनेशनल हवाई अड्डे का निर्माण पूर्ण करेंगे। हम अगले 5 वर्षों में 25 विश्वस्तरीय प्रमुख बस डिपो का निर्माण अथवा आधुनिकीकरण करेंगे। हम वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में रोप–वे सेवा विकसित करेंगे। हम 2,000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों में बस सुविधा सुनिश्चित करेंगे।

सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास –

हर बेघर को घर उपलब्ध करायेंगे। प्रदेश में माँ अन्नपूर्णा कैंटीन स्थापित करेंगे जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था करेंगे। प्रदेश में मछुआरा समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति करेंगे। प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना करेंगे, जिनमें ओबीसी युवाओं को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों को आवेदन के 15 दिनों के अंदर एवं नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था करेंगे। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रेप्यूट में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। संत रविदास मिशन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (ATS) स्थापित करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करेंगे। दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करेंगे। निर्माण श्रमिकों को ₹1लाख तक का कोलेटरल फ्री ऋण प्रदान करने के लिए उन्हें श्रमिक क्रेडिट कार्ड (एस.सी.सी.) देंगे। प्रत्येक

संभाग में मजदूरों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण को पूर्ण करेंगे। हम सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा प्रदान करेंगे। हम निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का विस्तार करते हुए मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान को।

सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं विकसित पर्यटन

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हम महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट में संत रविदास का बनारस में निषादराज गुह का श्रृंग्वेरपुर में एवं डॉ भीम राव अम्बेडकर की स्मृति में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करेंगे। लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किले को लाइट एवं साउंड शो जैसी सुविधाओं के माध्यम से एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में भव्य स्मारक का निर्माण पूर्ण करेंगे। महर्षि वाल्मीकि आश्रम एवं सीतामढ़ी स्थल का नवीनीकरण करके, इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। अयोध्या में श्री राम से संबंधित संस्कृति, शास्त्रों एवं धार्मिक तथ्यों पर शोध के लिए रामायण विश्वविद्यालय को स्थापित करेंगे। कुंभ मेला 2019 के सफल आयोजन के बाद हम महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ करेंगे। बुजुर्ग संत, पुजारियों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए एक विशेष बोर्ड बनाएंगे। मथुरा में सूरदास ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना करेंगे जो ब्रजभाषा साहित्य को पुनर्स्थापित करने में सहायक होगी। गोस्वामी तुलसीदास अवधी अकादमी की स्थापना करेंगे, जो समृद्ध अवधी साहित्य को समर्पित होगी। केशवदास बुंदेली अकादमी की स्थापना करेंगे, जो बुंदेली साहित्य को पुनर्स्थापित करने में सहायक होगी। संत कबीर दास भोजपुरी अकादमी की स्थापना करेंगे, जिससे हम देश भर के लोगों को इस समृद्ध भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की याद में हम लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी की स्थापना करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के लोक नृत्य, संगीत एवं रंगमच को लोकप्रिय बनाने एवं इनसे जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

श्री शाह ने उत्तर प्रदेश की जनता से मैं करबद्ध विनती करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति से परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए मजबूत नींव रखने का कार्य किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पुनः भारी बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाइये। हम उत्तर प्रदेश के गौरव को पुनः स्थापित करेंगे और हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को नंबर एक प्रदेश बनायेंगे, श्रेष्ठ प्रदेश बनायेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की व्यवस्था परिवर्तन विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विगल दो दशकों की राजनैतिक स्थिति का आंकलन करें तो उ0प्र0 में बसपा, सपा, कांग्रेस की सरकारें रहीं हैं इनके चुनावी घोषणा पत्र खोखले नारे साबित होते थे अराजकता, गुण्डाराज था। सड़क बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा की दुर्दशा थी। सत्ता बदलती थी, व्यवस्था वही स्थिर रहती थी। साम्प्रदायिकता, दंगा, बेरोजगारी से प्रदेश त्रस्त रहता था। इधर वैश्विक आपदा करोना के दो वर्षों के विनाशकारी प्रकोप के बाद भी उत्तर प्रदेश बदल रहा है सड़के, एक्सप्रेस–वे, सांस्कृतिक आस्था के केन्द्रों का विकास शिक्षा के ढ़ांचागत व्यवस्था परिवर्तन गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, युवा, सभी अपने जीवन स्तर को सुधारने में सुगमता पा रहे हैं। भाजपा का घोषणा पत्र एकात्म मानववाद के सिद्धांत को पूर्णता दे रहा है।

लक्ष्य अन्त्योदय, प्रण अन्त्योदय, पथ अन्त्योदय के शुभ संकल्प को दोहरा रहा है। जिसके कारण जन विश्वास प्रबल हो रहा है। भाजपा सरकार की पुनः वापसी की गारन्टी मिल रही है। क्योंकि भाजपा मनसा, वाचा, कर्मणा सबमें अडिग रहती है। इनके लिए एक सम्प्रदाय, जाति, परिवार, व्यक्ति का विकास मायने नहीं रखता ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के पक्षधर हैं। ■

यूपी फिर माँगे भाजपा सरकार

संदेश

सम्मानित भाइयों- बहनों ,

पाँच वर्ष पहले जब हम आपके पास आए थे, तब हमारा उत्तर प्रदेश विभिन्न समस्याओं के साथ जूझ रहा था - गुंडाराज, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भेद-भाव, बहन-बेटियाँ असुरक्षित, आस्था के स्मारकों का तिरस्कार इत्यादि। उस समय, भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया था की इन सभी समस्याओं का निवारण कर हम उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर करेंगे। इस संकल्प को सिद्ध करने हेतु, हमने पिछले 5 वर्षों में निरंतर प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है।

हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में बिजली, पानी, मकान, राशन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य किया है। 2017 के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अंतर्गत, हमने प्रदेश में चौमुखी विकास कर प्रदेश के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ने का प्रण लिया था। चाहे वह किसानों की क़र्ज़ माफ़ी हो, एम.एस.पी. पर अभूतपूर्व स्तर पर सरकार द्वारा फसलों की खरीद हो, 33 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, नए एक्सप्रेस-वे एवं अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो, श्रमिक वर्गों को आर्थिक सहयोग हो या महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी-रोमियो स्क्वॉड हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के सभी वर्गों के लिए, जो कहा था, वो करके दिखाया है। हमारे संकल्प काग़ज़ के फूल नहीं, पत्थर की लकीर होते हैं।

यह चुनाव सिर्फ विधानसभा का ही चुनाव नहीं है बल्कि यह चुनाव प्रदेश के विकास का चुनाव है। प्रदेश के एवं आपके भविष्य का चुनाव है। यह चुनाव आस्थाओं के सम्मान का चुनाव है, इस प्रदेश की गौरवशाली सनातन संस्कृति के सम्मान का चुनाव है। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए, आज हम फिर आपके सामने प्रदेश को नंबर 1 बनाने एवं निरंतर विकास का संकल्प लेकर आए हैं - यह लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022, प्रदेश की जनता के लिए, हमारा अगले 5 वर्षों का विज़न है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों और इस संकल्प पत्र को देख आप, आगामी चुनावों में फिर कमल का बटन दबाकर, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे और हम साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे।

वंदे मातरम्।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश

यूपी फिर माँगे भाजपा सरकार

संदेश

मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का कहना था कि 'भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति, अर्थनीति एवं समाज नीति ही देश के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। कोई भी देश अपनी जड़ों से कटकर विकास नहीं कर सका है'। भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,' इसी विचारधारा को दर्शाता है। 2017 में जब आपके स्नेह और विश्वास से हमारी सरकार बनी थी, तब हमारा उद्देश्य था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों का विकास हो।

भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयत्न किया कि जनता की आवाज़ हम तक पहुंचे। 2017 में हमने एक अनोखी पहल शुरू करी थी - 'यूपी के मन की बात', इसके आधार पर हमने अपना 'लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017' जारी किया था। पिछले 5 वर्षों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस संकल्प पत्र के प्रत्येक वचन को पूरा करने का प्रयास किया है; चाहे वह अवैध क़त्लखानों को बंद करना हो, गन्ना किसानों का बकाया चुकाना हो या 3 नए महिला पुलिस बटालियन की स्थापना हो माननीय श्री नरेंद्र मोदी और श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, पिछले 5 वर्षों में प्रदेश ने विकास की नई बुलंदियों स्थापित की है।

इसी वजह से, जनता की मांग के कारण, हमने अपने घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत 'यूपी नम्बर 1 - सुझाव आपका, संकल्प हमारा' अभियान से की, जिसके अंतर्गत करोड़ों यूपी वासियों ने हम तक, विभिन्न माध्यमों द्वारा, अपनी आकांक्षाएं पहुँचाई। जनता तक पहुँचने के लिए हमने प्रदेश के कोने-कोने में वीडियो वैन चलाई, हज़ारों सुझाव पेटियां पूरे प्रदेश में रखवाई, मिस्ड कॉल नम्बर जारी किया जिससे एक फ़ोन कॉल द्वारा लोग अपना संदेश हम तक पहुँचा सके और साथ ही हमारे कार्यकर्ता भी पहुँचे जनता के द्वार। विभिन्न सामाजिक समूहों (जैसे किसान, श्रमिक, व्यापारी, सेल्फ-हेल्प ग्रुप आदि) के साथ हमने बैठकें की ताकि हमारे संकल्प पत्र में उनके सुझाव भी हो।

यह केवल एक चुनाव का संकल्प पत्र नहीं है, बल्कि इस प्रदेश की जनता से हमारा संकल्प है, प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए हम सबका सामूहिक विज़न है। मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार आपने हम पर 5 वर्ष पहले भरोसा किया था, इस संकल्प पत्र के आधार पर आप एक बार और यूपी में कमल खिलाएँगे।

भारत माता की जय।

स्वतंत्र देव सिंह
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश

यूपी फिर माँगे भाजपा सरकार

संदेश

मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,

पिछले 5 वर्षों में भाजपा सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश बीमारु राज्य से आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन चुका है। आज हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के 95% से ज्यादा संकल्पों को पूर्ण कर लिया है, जिसका लाभ करोड़ों प्रदेश वासियों को मिला है। हमने किसानों के लिए ऋण माफ़ी, गरीब कल्याण कार्ड धारकों को राशन में तेल, दाल आदि भी कम दरों में प्रदान करने जैसे संकल्प लिए थे एवं उन्हें पूर्ण भी किया है।

भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आने वाले 5 वर्षों के लिए अपना संकल्प प्रदेश की 22 करोड़ से अधिक जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। भाजपा के इस संकल्प पत्र में प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं एवं आशाओं का समावेश है एवं प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की रुपरेखा है। आज हमें यह संकल्प पत्र प्रदेश की जनता के सामने रखते हुए गर्व हो रहा है। 'यूपी नंबर 1 - सुझाव आपका, संकल्प हमारा' अभियान के माध्यम से 'सबका साथ, सबका विकास एवं सबसे संवाद' के सूत्र को अपनाकर हमने प्रदेश के सभी वर्गों, समाजों से व्यापक संवाद एवं विचार-विमर्श कर उनकी आकांक्षाओं एवं सुझावों को सम्मिलित करने का कार्य किया है।

भाजपा द्वारा करीब एक महीने तक सम्पूर्ण प्रदेश में 'यूपी नंबर 1' अभियान चलाकर विभिन्न माध्यमों से जुड़ते हुए प्रदेश के करोड़ों लोगों से मिलकर उनकी आकांक्षाएं एकत्रित की गई है। हमारा यह संकल्प पत्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की अभिव्यक्ति का पत्र है। इस अभियान में सभी 403 विधानसभाओं के कुल मिलाकर 4 करोड़ से अधिक लोगों से जन-संपर्क, मिस्ड कॉल, बैठकें, सभा, सम्मेलनों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर उनके सुझावों को एकत्रित किया गया।

यह संकल्प पत्र उन करोड़ों लोगों की आवाज़ों के मंथन का परिणाम है, जिन्होंने मौजूदा शासन में विश्वास दिखाते हुए प्रदेश निर्माण की जिम्मेदारी में अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। भाजपा उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत आभारी है जिन्होंने इतनी भारी मात्रा में आकांक्षा एवं सुझाव हम तक पहुंचाएं। इस संकल्प पत्र को प्रकाशित करके हम फिर से सरकार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों की इन आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेते हैं।

जय हिन्द।

सुरेश कुमार खन्ना
अध्यक्ष, घोषणा पत्र समिति
भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश

"भाजपा ने कर के दिखाया, फिर करके दिखायेगी"

भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्रमें "अन्त्योदय" लक्ष्य के अनुरूप अपने संकल्प को पूरा किया है। विकास में पिछड़ा उत्तर प्रदेश आज निरन्तर प्रगति कर रहा है। जिसका तुलनात्मक व्याखा संकल्प पत्र में है।

2017 से पहले	2017 के बाद
किसानों की कर्जमाफी शून्य	₹36 हज़ार करोड़ से 86 लाख किसानों की कर्जमाफी
किसानों की मदद शून्य	पीएम किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में यूपी नंबर 1 2.5 करोड़ किसानों को ₹6,000 वार्षिक मदद
₹90 हज़ार करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान (2012-2017)	रिकॉर्ड ₹1.57 लाख करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान करके यूपी देश में अग्रणी
महिलाओं को मिला असुरक्षित वातावरण	महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण एवं वीरांगना अवंती बाई लोधी, वीरांगना ऊदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई महिला बटालियन का गठन
मुफ्त गैस शून्य	1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला पहला प्रदेश
गरीबों का हुआ शोषण, श्रमिकों को पोषण भत्ता शून्य पेंशन योजना ₹300/माह	गरीब कल्याण के लिए तत्पर 15 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज, 3 करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक ₹500 रुपये/माह का भत्ता एवं 98 लाख नागरिकों को ₹1,000/माह
युवाओं को नाम मात्र नौकरी	5 लाख युवाओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरियां एवं 3 लाख को संविदा पर नौकरियां
सरकारी स्कूलों की बदहाली	1.4 लाख सरकारी स्कूलों का कायाकल्प
एम्स का संचालन शून्य, सिर्फ़ 15 जिले में मेडिकल कॉलेज का संचालन	रायबरेली और गोरखपुर में एम्स का निर्माण एवं संचालन, 59 मेडिकल कॉलेज का निर्माण और संचालन
भ्रष्टाचार में नंबर 1, माफियाओं का राज	प्रदेश को दिया भ्रष्टाचार मुक्त शासन माफ़ियाओं की ₹1866 करोड़ की अवैध सम्पत्तियाँ जब्त
बीमारु प्रदेश, इन्वेस्टर्स का पलायन, कागजों में निवेश	उत्तर प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
2 एक्सप्रेस-वे एवं 2 एयरपोर्ट	5 एक्सप्रेस-वे एवं 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला प्रदेश
शौचालय निर्माण शून्य	2.61 करोड़ शौचालय का निर्माण, स्वच्छ भारत में यूपी नंबर 1

‘‘समग्र विकास अन्त्योदय’’ को समर्पित संकल्प’’

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने शवाब पर है पाँच वर्ष पहले भाजपा जंगलराज से मुक्ति दिलाकर सत्ता में आयी थी अपने किये वादे को इरादे से बदल कर, किये हुये संकल्पों को पूरा किया। आज प्रदेश सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी क्षेत्रों में बदलाव की बात जन–जन कर रहा है। अब दूसरी पारी में भाजपा नीति–नियति को स्पष्ट करते हुए भावी उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प ले लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सूत्र रूप में झलक रहा है, दूसरी तरफ हवा–हवाई समाजवादी वचन पत्र, लोभ, लालच, झूठ का वचनी मंजूषा जैसा ही प्रतीत हो रहा है। ये संकल्प भारत समेंत उत्तर प्रदेश की जनता की तकदीर बदलने में सक्षम दिख रहा है। संकल्प शब्द सार निम्न है –

समृद्ध कृषि

- अगले 5 वर्षों में हम **सभी किसानों** को सिंचाई के लिए **मुफ्त बिजली** उपलब्ध कराएंगे।
- हम **₹5,000 करोड़** की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत **सभी लघु एवं सीमांत किसानों** के लिए **बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब एवं टैंक निर्माण** के लिए अनुदान प्रदान करेंगे।
- हम **₹25,000 करोड़** की लागत के साथ **सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन** बनाकर प्रदेश भर में **छँटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चेम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर** आदि का निर्माण करेंगे।
- हम **₹1,000 करोड़** का **भामाशाह भाव स्थिरता कोष** बनाकर किसानों को **आलू, टमाटर एवं प्याज** जैसी सभी फसलों का **न्यूनतम मूल्य** सुनिश्चित करेंगे।
- हम **₹5,000 करोड़** की लागत के साथ **गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन** के अंतर्गत **चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण** करेंगे। साथ ही, स्थानीय मांग के अनुसार प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करेंगे।
- हम अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर **गेहूं एवं धान** की खरीद को और मजबूत करेंगे।
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि **गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान प्राप्त** हो, और देरी से होने वाले भुगतान के लिए मिलों से ब्याज वसूल करके गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा।
- हम अगले 5 वर्षों में **₹1,000 करोड़** की लागत द्वारा प्रदेश को, **नन्द बाबा दुग्ध मिशन** के अन्तर्गत, दुग्ध उत्पादन में **अग्रणी राज्य** बनाए रखेंगे। इसके लिए हम गाँवों में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गाँव में ही

उनके दूध के **उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा** उपलब्ध कराएँगे।

- हम **प्रधानमंत्री कुसुम योजना** के अंतर्गत किसानों को **सोलर पंप** प्रदान करते रहेंगे। साथ ही, हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए **सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली** को बेचने की उचित व्यवस्था करेंगे।
- हम **4,000 नए फसल-विशिष्ट एफ.पी.ओ. (FPO)** स्थापित करके, प्रत्येक एफ.पी.ओ. को **₹18 लाख** तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- हम **मिशन प्राकृतिक खेती** के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे।
- हम प्रदेश में **6 मेगा फूड पार्क** विकसित करेंगे।
- हम प्रदेश में **निषादराज बोट सब्सिडी योजना** शुरु करेंगे, जिसके अंतर्गत मछुआरों को **₹1 लाख** तक की नाव **40% सब्सिडी** पर उपलब्ध कराएंगे। हम मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए **25% तक की सब्सिडी** प्रदान करेंगे एवं 6 अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी स्थापित करेंगे।

सशक्त नारी

- हम **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** के अंतर्गत वित्तीय सहायता को **₹15 हजार से बढ़ाकर ₹25 हजार** तक करेंगे।
- हम **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना** के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह हेतु **₹1 लाख तक** की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- हम **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** के सभी लाभार्थियों को **होली तथा दीपावली पर 2 मुफ्त एल.पी.जी. सिलेंडर** प्रदान करेंगे।
- हम **60 वर्ष** से अधिक **उम्र की महिलाओं** के लिए **सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा** की व्यवस्था करेंगे।
- हम ₹1,000 करोड़ की लागत के साथ **मिशन पिंक टॉयलेट** शुरु करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी **सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण एवं रखरखाव** सुनिश्चित करेंगे।
- हम **विधवा एवं निराश्रित महिलाओं** के लिए पेंशन को बढ़ाकर **₹1,500 प्रतिमाह** करेंगे।
- हम **3 नई महिला बटालियन** के नेटवर्क का विस्तार कर उसे दोगुना करते हुए **महिलाओं की सुरक्षा** और भी सुनिश्चित करेंगे।
- हम **सभी सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों** के पास **सी.सी.टी.वी. कैमरे** लगवाएंगे एवं **3,000 पिंक पुलिस बूथ** स्थापित करेंगे।
- हम **₹5,000 करोड़** की लागत के साथ **अवन्ति बाई लोधी स्वयं सहायता समूह (SHG) मिशन** शुरु करेंगे, जिसके अंतर्गत 5 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाई जाएंगी।
- हम स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली लगभग **1 करोड़ महिलाओं** को **आत्मनिर्भर एस.एच.जी. क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से **₹1 लाख तक का ऋण** न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराएंगे।
- हम **लोक सेवा आयोग (UPPSC)** सहित सभी **सरकारी नौकरियों** में महिलाओं की संख्या को **दोगुना** करेंगे।
- हम कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु **रानी लक्ष्मी बाई योजना** के अंतर्गत **मुफ्त स्कूटी** वितरित करेंगे।
- हम सभी **आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं** एवं **स्वास्थ्य सखियों** को आयुष्मान भारत के अंतर्गत **स्वास्थ्य बीमा,** मिशन मोड पर प्रदान करेंगे।
- हम **₹500 करोड़** की लागत के साथ **स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम** शुरु करेंगे, जिसके अंतर्गत चुनी गई **महिला एथलीटों को ₹5 लाख** तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

सुगम शिक्षा

- हम **ऑपरेशन कायाकल्प** के अंतर्गत सभी **प्राथमिक विद्यालयों** में बच्चों के **अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बेंच** आदि उपलब्ध कराएंगे तथा उन्हें **स्मार्ट विद्यालयों** के रूप में विकसित करेंगे।
- हम **माध्यमिक** विद्यालय नवीनीकरण मिशन शुरु करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के **30,000 माध्यमिक विद्यालयों** के बुनियादी ढांचे का **नवीनीकरण** किया जाएगा -
  - ऑडियो-वीडियो प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लास रुम का निर्माण करेंगे
  - पुस्तकालय का निर्माण करेंगे
  - कंप्यूटर लैब, साइंस लैब एवं आर्ट रुम का निर्माण करेंगे
  - वाई-फाई की व्यवस्था करेंगे।
- हम **हायर एजुकेशन रेनोवेशन मिशन** शुरु करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के कॉलेजों (आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक समेत) के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा -
  - प्रत्येक महाविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट क्लास रुम की व्यवस्था करेंगे
  - एस.टी.ई.एम.(STEM) पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण की व्यवस्था करेंगे
  - वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि **हर मण्डल में** कम से कम **एक विश्वविद्यालय** हो।
- हम **अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर** एवं **वर्ल्ड क्लास** सुविधाओं के साथ **विश्वविद्यालयों के निर्माण** को पूरा करेंगे -
  - अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय
  - आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय
  - सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय
  - लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस
  - अयोध्या में आयुर्वेद के लिए आयुष शैक्षणिक संस्थान
  - गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय
  - प्रयागराज में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेशनल लॉ विश्वविद्यालय
  - मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय।
- हम लखनऊ एवं नोएडा में डिजिटल अध्ययन अकादमी की स्थापना करेंगे।
- हम **₹2,500 करोड़** की लागत के साथ **विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम** शुरु करेंगे, जिसके अंतर्गत युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक ब्लॉक में एक **आई.टी.आई.** की स्थापना करेंगे।
- हम सभी महापुरुषों तथा **स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों** की जीवन गाथाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।

सक्षम युवा

- हमने पिछले 5 वर्षों में **3 करोड़** से अधिक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्षों में, हम **हर परिवार** में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेंगे।
- हम प्रदेश सरकार की **सभी विभागीय रिक्तियों** को **शीघ्रता** से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम **इच्छुक युवाओं को अभ्युदय योजना** के अंतर्गत यू.पी.एस.सी., यू.पी.पी.एस.सी., एन.डी.ए., सी.डी.एस., जे.ई.ई., एन.आई.आई.टी., टी.ई.टी., क्लैट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के

लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेंगे।

- हम **स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना** के अंतर्गत **2 करोड़ टैब्लेट अथवा स्मार्टफ़ोन** वितरित करेंगे।
- हम **मेजर ध्यानचंद खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन** शुरु करेंगे, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों समेत **पूरे प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर** का निर्माण एवं नवीनीकरण करेंगे।
- हम सभी **सरकारी खेल प्रशिक्षण अकादमियों** में प्रशिक्षित प्रत्येक खिलाड़ी को **मुफ्त स्पोर्ट्स किट एवं उपकरण** वितरित करेंगे।
- हम **प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम एवं खेल मैदान स्थापित** करेंगे।
- हम **हर ब्लॉक** में क्रिकेट प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, साथ ही प्रदेश में विभिन्न **खेलों के लिए अकादमी** की स्थापना करेंगे।
- हम खिलाड़ियों को **वित्तीय सहायता** उपलब्ध कराएंगे।
- हम स्कूल और कॉलेज स्तर पर **योग शिक्षकों** की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे।

स्वस्थ प्रदेश

- हम प्रदेश के **हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों** की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करेंगे।
- हम लगभग **₹30,000 करोड़** के निवेश के साथ **6 धन्वंतरि मेगा हेल्थ पार्क** स्थापित करेंगे, जिनके अंतर्गत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य एवं सर्जिकल उपकरणों और दवाओं जैसी चिकित्सीय सुविधाओं के उत्पादन का विस्तार कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
- हम **₹10,000 करोड़ की लागत के साथ महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन** के अंतर्गत प्रदेश में हर स्तर पर सुचारु स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण करेंगे।
- हम मिशन जीरो की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, ज़ीका वायरस, जापानी एन्सेफलाइटिस एवं कालाजार जैसी वेक्टर बोर्न बीमारियों को **मिटाने** की पहल करेंगे।
- हम अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस **एम्बुलेंस की संख्या को दोगुना** करेंगे।
- हम प्रत्येक जिले में **डायलिसिस केंद्र** स्थापित कर किडनी रोगियों को लाभ पहुंचाएंगे।
- हम प्रदेश में एम.बी.बी.एस. जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए **सीटों की संख्या को दोगुना** करेंगे।
- हम **6,000 डॉक्टरों एवं 10,000 पैरा-मेडिकल स्टाफ** की नियुक्ति शीघ्र करेंगे।
- हम प्रदेश में **जन औषधि केंद्र के नेटवर्क का विस्तार कर सभी नागरिकों को कम कीमत में ज़रूरी दवाइयां** उपलब्ध कराएंगे।
- हम **2025 तक उत्तर प्रदेश को टी-बी मुक्त** बनाएंगे।

सुशासन

- हम **गुंडे, अपराधी और माफ़िया के खिलाफ कार्यवाही** इसी दृढ़ता से आगे भी जारी रखेंगे।
- हम प्रदेश के सभी नागरिकों को 339 सरकारी सेवाएं निश्चित अवधि प्रदान कर रहे हैं। हम इसमें और वृद्धि करेंगे।
- हम तहसील स्तर पर **तहसील दिवस** के दौरान **जनता दरबार** का आयोजन जारी रखेंगे।
- हम प्रदेश के सभी 18 मण्डलों में **एंटी-करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट** स्थापित करेंगे।
- हम मेरठ में **कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर** स्थापित करेंगे।
- हम लव जिहाद करने पर कम से कम **10 वर्षों की**

सजा और ₹1 लाख के जुर्माने का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे।

- हम आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए देवबंद में **एंटी-टेररिस्ट कमांडो सेंटर** का निर्माण पूर्ण करेंगे तथा **मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर एवं बहराइच** में इसी तरह **एंटी-टेररिस्ट कमांडो सेंटरों** का निर्माण करेंगे।
- हम प्रदेश के **प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक साइबर हेल्प डेस्क (सी.एच.डी.)** स्थापित करेंगे।
- हम सभी **पुलिस कर्मियों (महिलाओं एवं पुरुषों) के लिए बैरक की व्यवस्था** उपलब्ध कराएंगे।
- हम **पुलिस विभाग के कर्मियों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए भवनों का निर्माण, मरम्मत आदि का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण** करेंगे।

अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास

- हम उत्तर प्रदेश को देश की **नंबर 1** अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम उत्तर प्रदेश की **प्रति व्यक्ति आय को दोगुना** करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम उत्तर प्रदेश में लगभग **₹10 लाख करोड़** के **निवेश** को आकर्षित करेंगे।
- हम **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को **नंबर 1** बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम **अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन** शुरु करके सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण करेंगे।
- हमने पिछले 5 वर्षों में **एक जनपद एक उत्पाद योजना** शुरु करके हर जिले के एक उत्पाद को पहचान दी एवं 25 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्षों में निर्यात एवं **रोजगार अथवा स्वरोजगार** के अवसरों को **दोगुना** करेंगे।
- हम बुंदेलखंड में **जनरल बिपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर** का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करेंगे।
- हम प्रदेश में **5 विश्व स्तरीय एक्जीबिशन** और **अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर** स्थापित करेंगे।
- हम **सभी एक्सप्रेस-वे** के निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करेंगे जिससे **5 लाख युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार** के अवसर प्रदान होंगे। इसके अंतर्गत **हैंडलूम, फ़ूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज प्लांट, रसायन, दवा एवं मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग आदि को बढ़ावा देंगे।**
- हम प्रदेश में **3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क** स्थापित करेंगे।
- हम **आत्मनिर्भर युवा स्टार्ट-अप मिशन** बनाकर **10 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार** के अवसर प्रदान करेंगे और हम **स्टार्ट-अप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को नंबर 1** बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम **तीन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर** स्थापित करके **4 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार** के अवसर प्रदान करेंगे।
- हम **कानपुर में मेगा लेदर पार्क** स्थापित करके 2 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
- हम अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाकर **5 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार** के अवसर प्रदान करेंगे।
- हम **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME)** के लिए **6 औद्योगिक पार्कों** के निर्माण को पूरा करेंगे जहां लाखों युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
- हम **संभाग स्तर पर आईटी पार्क** की स्थापना कर, लाखों रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
- हम मछली उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के

लिए जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करेंगे।

आधारभूत संरचना

- हम **बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना** शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गाँवों का समग्र विकास करेंगे -
  - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ेंगे
  - गाँवों में पक्के ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था बनाकर जल निकासी की समस्या को दूर करेंगे
  - प्रत्येक ग्राम पंचायत में बस स्टॉप का निर्माण करेंगे
  - गाँवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे
  - हर ग्राम पंचायत में शत-प्रतिशत इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे।
- 2024 तक हम **जल जीवन मिशन** के अंतर्गत, प्रदेश के **हर घर को नल से स्वच्छ जल** उपलब्ध कराएंगे।
- हम अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का रिकॉर्ड समय में निर्माण पूर्ण करेंगे -
  - 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस-वे
  - एलिवेटेड कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे
  - गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे
  - बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे
  - बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे।
- हम यू.पी.एस.आर.टी.सी. के अंतर्गत **बसों का आधुनिकीकरण** करेंगे एवं बस में पैनिक बटन की सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
- हम **काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी** और **प्रयागराज मेट्रो परियोजनाओं** पर काम करेंगे।
- हम **एविएशन उद्योग** में रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए **जेवर को एक एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर** के साथ रखरखाव और ऑपरेशन (MRO) हब के रूप में विकसित करेंगे।
- हम **अयोध्या इंटरनेशनल हवाई अड्डे** का निर्माण पूर्ण करेंगे।
- हम रेल मार्ग, जल मार्ग और हवाई अड्डे के निर्माण को डबल इंजन की सरकार द्वारा और गति देंगे।
- हम अगले 5 वर्षों में **25 विश्वस्तरीय प्रमुख बस डिपो का निर्माण अथवा आधुनिकीकरण करेंगे।**
- हम **वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में रोप-वे सेवा विकसित** करेंगे।
- हम **2,000 नई बसों** के माध्यम से सभी **गाँवों में बस सुविधा** सुनिश्चित करेंगे।

सबका साथ सबका विकास

- **हर बेघर को घर** - हम सभी गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जाति, पिछड़ा व वंचित एवं अन्य गरीब परिवारों को **आवासीय पट्टे की भूमि** तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- हम प्रदेश में **माँ अन्नपूर्णा कैंटीन** स्थापित करेंगे, जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था करेंगे।
- हम पिछड़ा वर्ग समुदायों के सदस्यों को आवेदन के **15 दिनों** के अंदर एवं नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ **जाति प्रमाण पत्र** वितरण करने की व्यवस्था करेंगे।
- हम प्रदेश में **मछुआरा समुदाय के युवाओं** के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए नदियों के पास **लाइफ गार्ड** की नियुक्ति करेंगे।
- हम **प्रशिक्षण अकादमियों** की स्थापना करेंगे, जिनमें **ओ.बी.सी. युवाओं** को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए **मुफ्त कोचिंग** प्रदान की

जाएगी।

- हम अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों को आवेदन के **15 दिनों** के अंदर एवं नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ **जाति प्रमाण पत्र** वितरण करने की व्यवस्था करेंगे।
- हम **नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रेप्यूट** में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- हम **संत रविदास मिशन** के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए **राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (ATS)** स्थापित करेंगे।
- हम **ई.डब्ल्यू.एस. कल्याण बोर्ड** का गठन कर ई.डब्ल्यू.एस. के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण एवं **10% ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण** के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।
- हम **वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह** करेंगे।
- हम **दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500** प्रतिमाह करेंगे।
- हम निर्माण श्रमिकों को **₹1 लाख तक का कोलैटरल फ्री ऋण** प्रदान करने के लिए उन्हें **श्रमिक क्रेडिट कार्ड (एस.सी.सी.)** देंगे।
- हम प्रत्येक संभाग में मजदूरों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए **अटल आवासीय विद्यालय** के निर्माण को पूर्ण करेंगे।
- हम सभी निर्माण श्रमिकों को **मुफ्त जीवन बीमा** प्रदान करेंगे।
- हम निर्माण श्रमिकों के बच्चों को **स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा** प्रदान करेंगे।
- हम **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना** का विस्तार करते हुए **मुफ्त कौशल विकास** प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- हम सभी शहरों में **टाउन वेंडिंग कमेटी** की स्थापना करेंगे एवं नए **वेंडिंग जोन** बनाएंगे।
- हम सभी **स्ट्रीट हॉकर्स एवं ई-कॉमर्स** से जुड़े डिलीवरी बॉयज **को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना** से जोड़ेंगे।
- हम ई-कॉमर्स से जुड़े डिलीवरी बॉयज को सरकार की **विभिन्न लाभकारी योजनाओं** में शामिल करेंगे।
- हम सभी शहरों में **ई-रिक्शा एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट** सुविधाओं के साथ ऑटो रिक्शा स्टैंड एवं पार्किंग स्थल बनाएंगे।
- हम सभी ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत **₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान** करेंगे।

सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन

- हम **महर्षि वाल्मीकि** का चित्रकूट में, **संत रविदास** का बनारस में, **निषादराज गुह्य** का श्रृंग्वेरपुर में एवं **डॉ भीम राव अम्बेडकर** की स्मृति में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करेंगे।
- हम लखनऊ में **महाराजा बिजली पासी** किले को लाइट एवं साउंड शो जैसी सुविधाओं के माध्यम से एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे।
- हम बहराइच में **महाराजा सुहेलदेव** की स्मृति में भव्य स्मारक का निर्माण पूर्ण करेंगे।
- हम **महर्षि वाल्मीकि** आश्रम एवं सीतामढ़ी स्थल का नवीनीकरण करके, इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे।
- हम अयोध्या में श्री राम से संबंधित संस्कृति, शास्त्रों एवं धार्मिक तथ्यों पर शोध के लिए **रामायण विश्वविद्यालय** को स्थापित करेंगे।
- हम कुंभ मेला 2019 के सफल आयोजन के बाद **महाकुंभ 2025** का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ करेंगे।
- हम बुजुर्ग संतों, पुजारियों एवं पुरोहितों के समग्र

कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए एक **विशेष बोर्ड** बनाएंगे।

- हम **ऑनलाइन एकीकृत** मंदिर सूचना प्रणाली (ITIS) लॉन्च करेंगे, जो मंदिरों का विवरण प्रदान करेगी और जिसमें उनके इतिहास एवं रूट मैप्स जैसी जानकारी शामिल होगी।
- हम छात्रों के लिए **मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत** प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- हम मथुरा में **सूरदास ब्रजभाषा अकादमी** की स्थापना करेंगे, जो ब्रजभाषा साहित्य को पुनर्स्थापित करने में सहायक होगी।
- हम **गोस्वामी तुलसीदास अवधी अकादमी** की स्थापना करेंगे, जो समृद्ध अवधी साहित्य को समर्पित होगी।
- हम **केशवदास बुंदेली अकादमी** की स्थापना करेंगे, जो बुंदेली साहित्य को पुनर्स्थापित करने में सहायक होगी।
- हम **संत कबीर दास भोजपुरी अकादमी** की स्थापना करेंगे, जिससे हम देश भर के लोगों को इस समृद्ध भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- हम **₹10,000 करोड़** के निवेश के साथ नोएडा में **ग्रैंड फिल्म सिटी** का निर्माण पूर्ण करेंगे।
- हम प्रदेश में शूट होने वाली हिंदी, भोजपुरी, अवधी एवं ब्रज भाषा की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए **₹2 करोड़** तक की नकद प्रोत्साहन राशि, बिजली सब्सिडी एवं टैक्स सब्सिडी प्रदान करेंगे।
- हम **लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी** की स्थापना करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के लोक नृत्य, संगीत एवं रंगमंच को लोकप्रिय बनाने एवं इनसे जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

जन गण मंगलदायक बजट

भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्तव बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। देश की अर्थव्यवस्था महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उभरकर जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है वह हमारे देश की दमदार मजबूती को दर्शाती है। यह बात केन्द्री य वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीजय बजट 2022–23 पेश करते हुए कही।

केन्द्रीय बजट 2022-2023

वर्ष 2014 से ही सरकार देश के नागरिकों, विशेषकर गरीबों एवं हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करती रही है और इसके साथ ही लोगों को आवास, बिजली, रसोई गैस मुहैया कराने तथा जल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, सरकार ने वित्तीय समावेश एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके साथ ही सरकार ने समस्त अवसरों का उपयोग करने में गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

वित्त मंत्री ने बताया कि **'आत्मनिर्भर भारत'** विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्टरों में दिए जा रहे उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन पर व्यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है जिनमें 60 लाख नए रोजगारों को सृजित करने के साथ–साथ अगले पांच वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन के मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया के स्वा्मित्व् के रणनीतिक हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है, एनआईएनएल (नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) के रणनीतिक साझेदार का चयन हो चुका है, एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द ही आने की आशा है और अन्य संबंधित प्रस्ताव भी वर्ष 2022–23 के लिए प्रक्रियाधीन हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास को निरंतर नई गति दे रहा है इसमें इस समानांतर पथ का उल्लेख किया गया है: (1) अमृत काल के लिए ब्लू प्रिंट, जो अत्याधुनिक एवं समावेशी है और जिससे हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी, और (2) अत्याधुनिक अवसंरचना के लिए व्यापक सार्वजनिक निवेश, भारत/100 के लिए तैयार होना और इसका मार्गदर्शन पीएम गतिशक्ति द्वारा किया जाएगा और यह बहु–विध दृष्टिकोण में सामंजस्य से लाभान्वित होगा। इस समानांतर पथ पर आगे बढ़ते हुए वित्त मंत्री ने निम्न लिखित चार प्राथमिकताओं को

रेखांकित किया:
- पीएम गतिशक्ति
- समावेशी विकास
- उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव, और जलवायु कार्रवाई
- निवेश का वित्तपोषण करना

वित्त मंत्री ने पीएम गतिशक्ति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह आर्थिक विकास सतत विकास के लिए एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को सात इंजनों यथा सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्गों, और लॉजिस्टिक्स संबंधी अवसंरचना से तेज गति मिल रही है। सभी सातों इंजन आपस में मिलकर देश की अर्थव्यावस्था को आगे बढ़ाएंगे। इन इंजनों को ऊर्जा पोषण, आईटी संचार, व्यापक जल एवं सीवेज, और सामाजिक अवसंरचना की पूरक भूमिकाओं से आवश्यक सहयोग मिल रहा है।

इस दृष्टिकोण को स्वच्छ ऊर्जा एवं **'सबका प्रयास'** यानी केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र के मिले–जुले प्रयासों से नई गति मिल रही है जिससे सभी, विशेषकर युवाओं को व्यापक रोजगार एवं उद्यमिता अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

इसी तरह वर्ष 2022–23 में एक्सप्रेस–वे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टेर प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों एवं वस्तुओं की त्वरित आवाजाही संभव हो सके। वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000

बजट, भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास - नरेन्द्र मोदी

ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानव के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट More Infrastructure, More Investment, More Growth, और More Jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है Green Jobs का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है।

मैं पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं, जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानव की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुणा बढ़ा दिया है।

जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदेभारत ट्रेन हों, डिजिटल करेन्सी हो, banking के क्षेत्र में digital units हों, 5G services का रोल आउट हो, National Health के लिए digital ecosystem हो, इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब–दलित–पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा।

इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है– गरीब का कल्याण, हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही

आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी, और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव हैं, बॉर्डर के गांव हैं। जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है। जो देश की सिक्युरिटी के लिए भी आवश्यक है। उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी।

भारत के कोटि–कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ–साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमे मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं की कृषि लाभप्रद हो, इसमें नये अवसर हों। नए एग्रीकल्चर स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। MSP खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

कोरोना काल में MSME यानि हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे। अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। साढ़े 7 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही, छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे।

मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस People Friendly और Progressive बजट के लिए बहुत–बहुत बधाई देता हूं। ■

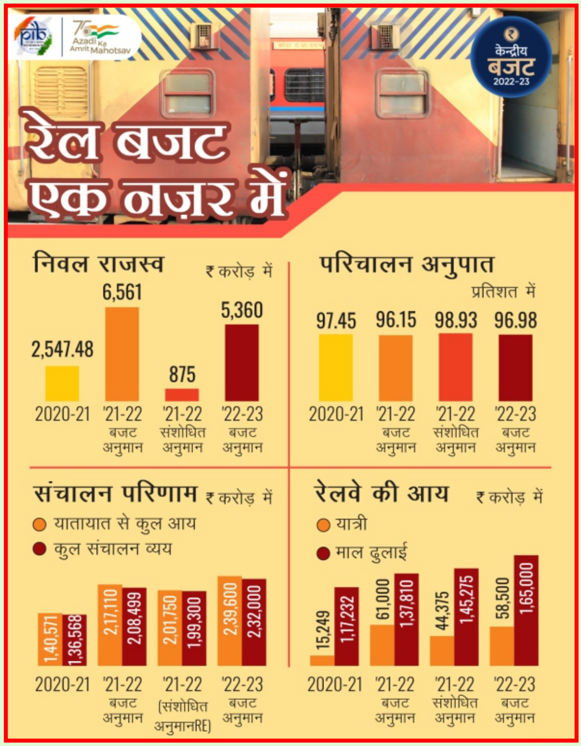

किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा और सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के तौर पर वित्तपोषण के अभिनव तरीकों के जरिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड के जरिए चार स्थानों पर मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए वर्ष 2022–23 में ठेके दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में 'एक स्टेशन–एक उत्पाद' अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा, ताकि स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को आवश्यक मदद मिले सके। इसके अलावा, **'आत्मनिर्भर भारत'** के तहत वर्ष 2022–23 में 2,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को **'कवच'** के अंतर्गत लाया जाएगा जो सुरक्षा और क्षमता वर्धन के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले तीन वर्षों में बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्रियों को बेहतरीन यात्रा अनुभव दिलाने वाली नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी और इसके साथ ही मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया

गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं की प्रगति का बजट- स्वतंत्रदेव सिंह

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय बजट देश की खुशहाली और उत्तर प्रदेश के विकास को और भी गति देने वाला बजट है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं की प्रगति का बजट है। यह सबके लिए हितकारी बजट है। बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश को इस बजट में सबसे ज्यादा मिला है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

श्री सिंह ने कहा कि किसानों के लिए बजट में एमएसपी का कोटा 10 फीसदी बढ़ाया गया है। इससे किसानों की उपज को उनका सही दाम मिलने की सुरक्षा मिली है। गंगा किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणा आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है। केन–बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट में की गई घोषणा का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसानों को ही मिलने वाला है। केन–बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बजट में की गई किसान हितैषी घोषणाओं से किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी।

गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान दिए जाने की घोषणा गरीब हितैषी सरकार के संकल्प को सिद्ध करने वाली है। यूपी के सर्वाधिक लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। सरकार ने प्रदेश में 43 लाख लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। हर घर को नल से जल की सुविधा की योजना के तहत की गई घोषणा से भी उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवार लाभान्वित होंगे। इससे उन्हें साफ पीने का पानी घर पर ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की घोषणा से गांव के लोग सशक्त होंगे। उनके दरवाजे पर ही उन्हें बैंकिंग की सुविधा मिलेगी।

सरकार की कर्मचारी हितैषी घोषणा के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है।

एक स्टेशन एक उत्पाद की घोषणा से देश के लाखों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। देश के उत्पादों को नया मंच मिलेगा। 400 नई वंदेभारत ट्रेनों से विकास को नई दिशा मिलेगी। सबसे ज्यादा ट्रेन भी यूपी से गुजरेगी। राजमार्गों के विकास, कार्गो और लॉजिस्टिक्स पार्कों के निर्माण से भी नौकरियां आएंगी। इसका भी सर्वाधिक लाभ यूपी को मिलने वाला है।

स्टार्टअप प्रोत्साहन, एमएसएमई को प्रोत्साहन, 80 लाख नई नौकरियां युवाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगी। इससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने में मदद मिलेगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी और स्कूली शिक्षा में डिजिटल कंटेंट और शैक्षिक चैनलों के प्रसारण बढ़ाने की घोषणा भी बहुत ही उपयोगी है। कोरोना के कारण बदली परिस्थितियों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, 5जी शुरू करने की घोषणा इसके साथ ही सस्ते डेटा को लेकर की गई घोषणा से भी काफी लाभ होगा। मानसिक स्वास्थ मिशन की घोषणा भी नया कदम है। आंगनबड़ियों का उन्नयन, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम भी काफी मददगार होंगे। केंद्र की सभी योजनाओं में सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को होने वाला है। ▪

जाएगा जिसके तहत प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। फसल आकलन, भूमि रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण, और कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए **'किसान ड्रोन'** के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक तर्कसंगत एवं व्याप्भक योजना लागू की जाएगी, ताकि देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

2023 को **'अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान वर्ष'** घोषित किए जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कटाई उपरांत मूल्य वर्धन के साथ–साथ घरेलू खपत बढ़ाने, देश–विदेश में बाजरा उत्पोदों की ब्रांडिंग करने को पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली केन–बेतवा संपर्क

परियोजना को कियान्वित किया जाएगा जिसका उद्देश्य किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट पनबिजली, और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्धं कराना है। इस परियोजना के लिए संशोधित बजट अनुमान 2021–22 में 4,300 करोड़ रुपये और वर्ष 2022–23 में 1,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, पांच नदी संपर्कों यथा . दमनगंगा–पिनजाल, पार–तापी–नर्मदा , गोदावरी–कृष्णा, कृष्णां–पेन्नार और पेन्नार–कावेरी की मसौदा डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और लाभार्थी राज्यों के बीच आम सहमति होने के साथ ही केन्द्र सरकार इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता दे देगी।

वित्त मंत्री ने यह बात रेखांकित की कि आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना **(ईसीएलजीएस)** के तहत 130 लाख से भी अधिक एमएसएमई को अत्यंत आवश्यक अतिरिक्ती ऋण मुहैया कराया गया है, जिससे उन्हें महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि विशेषकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा मुहैया कराए जाने वाली आतिथ्य एवं संबन्धित सेवाओं का कुल कारोबार अभी तक अपने महामारी –पूर्व स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। इन पहलुओं पर विचार करने के बाद ईसीएलजीएस की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। इसके तहत अतिरिक्त राशि को विशेषकर आतिथ्य एवं संबंधित उद्यमों के लिए निर्दिष्ट किया जा रहा है।

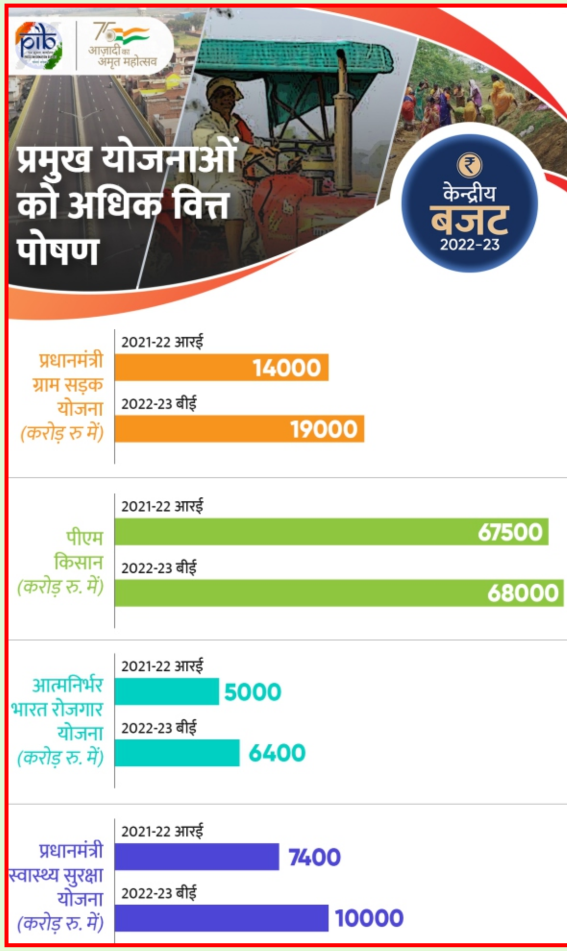

इसी तरह आवश्यक धनराशि मुहैया कराकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना में संशोधन किया जाएगा। इससे सूक्ष्मी एवं लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्ती ऋण सुलभ होगा और रोजगार अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्धन एवं त्वरण एमएसएमई प्रदर्शन (आरएएमपी) कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ताकि एमएसएमई सेक्टर को और भी अधिक मजबूत, प्रतिस्पर्धी एवं प्रभावकारी बनाया जा सके।

उद्यम, ई–श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा और उनका दायरा बढ़ाया जाएगा।

'कौशल विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' विषय के बारे में

'आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट- योगी'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा एक सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके खासतौर पर, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

कोरोना काल खंड में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यह बढ़ाने वाला बजट है। बजट में खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह वर्षों से चली आ रही किसानों की मांग को पूरा करता है। साथ ही प्रधानमंत्री के उस संकल्प जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां भारत और स्वभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के युवाओं को और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न अनुप्रयोगों के जरिए **'ड्रोन शक्ति'** को सुविधाजनक बनाने के साथ–साथ 'एक सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस)' के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों में स्थित चुनिंदा आईटीआई में कौशल बढ़ाने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में आवश्यक चिंतन–मनन को बढ़ावा देने वाले आवश्यक कौशल को प्रोत्साहन देने, रचनात्मकता की गुंजाइश के लिए विज्ञान एवं गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं और उन्नत शिक्षण माहौल के लिए 75 कौशल ई–लैब वर्ष 2022–23 में स्थापित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि महामारी के कारण स्कूलों को बंद कर देने से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों की लगभग 2 वर्षों की औपचारिक शिक्षा का नुकसान हुआ है। इनमें से अधिकतर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इसे ध्योन में रखते हुए पूरक शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ शिक्षा सुलभ कराने हेतु एक मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए 'पीएम ई–विद्या' के 'एक कक्षा–एक टीवी चैनल' कार्यक्रम का विस्तार 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा और इससे सभी राज्य कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे।

देशभर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्योक्तिगत तौर पर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय गुणवत्ता पूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित **हब–स्पोक** मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें हब भवन अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता से युक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब–स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत **'नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम'** के लिए एक ओपन प्लेटफार्म चालू किया जाएगा। इसमें चिकित्सा कर्मी एवं स्वास्थ सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ स्टाफ पहचान, कंसेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ ए सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ की समस्या बढ़ा दी है।

और उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ–साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है, जो महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के लोन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान और भी ऐसे प्रावधान हैं, नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान है।

'ओडीओपी की तर्ज पर ओएसओपी का लाभ मिलेगा– सीएम'

मुख्यमंत्री ने कहा कि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा आवागमन को और आसान बनाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा, जिससे स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार की एक जिला, एक उत्पाद योजना के तर्ज पर नई शुरू होने वाली एक स्टेशन, एक उत्पाद योजना का लाभ भी स्थानीय लोगों को मिलेगा।

'गौतमबुद्धनगर में बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को भी मिलेगा लाभ'

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर सरकार की दूरदर्शिता परिलक्षित होती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, कार्गो के निर्माण और भी अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यह देश की अर्थव्यवस्था को एक नई उचाईयां देगा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

'भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना'

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2021–22 में वैश्विक महामारी कोरोना के बाद भी भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ 32 साल बाद 9.2 फीसदी है। यह अपने आप में बड़ी बात है। भारत की अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक और शानदार प्रदर्शन किया है। इस लिहाज से भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के कारण ही संभव हो पाया है।■

गुणवत्ता परक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच स्थापित करने के लिए एक **'नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम'** शुरू किया जाएगा। इसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर का एक नेटवर्क होगा, जिसमें एनआईएमएचएएनएस एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और इंटरनेशनल इंस्टीमट्यूट फॉर इंफोर्मेशन टेक्नोवलॉजी – बंगलूरू (आईआईआईटीबी) तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि हर घर, नल से जल के लिए 2022–23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है और इसमें से 5.5 करोड़ परिवारों को पिछले 2 वर्षों में नल का पानी उपलब्ध करा दिया गया है।

इसी प्रकार वर्ष 2022–23 में ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित एवं पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

उत्तर–पूर्व परिषद के माध्यम से **'उत्तर–पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल'** नामक एक नई योजना चलाई जाएगी। इससे पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप उत्तर–पूर्व की जरूरतों के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं और

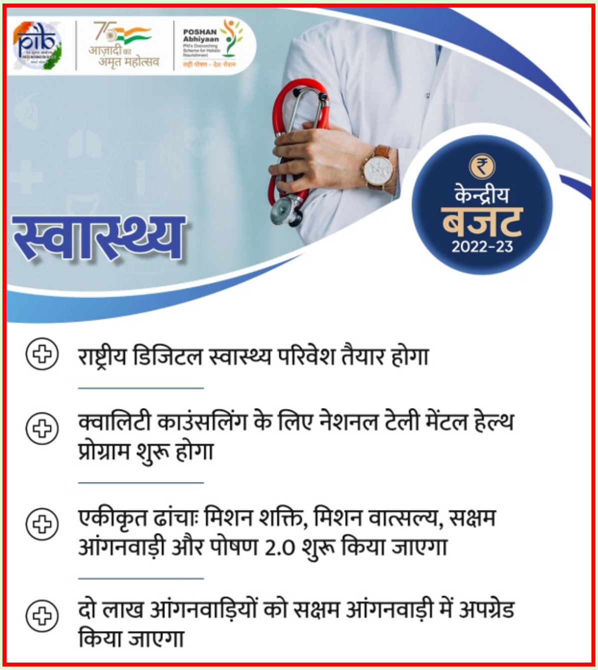

गांव, गरीब, किसानों और नौजवानों का बजट- केशव मौर्य

श्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय बजट को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि यह देश को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के साथ विकास को रफ़्तार देगा। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मोदी सरकार का यह बजट क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बजट है। 'मोदी हैं तो मुमकिन है' को चरितार्थ करते हुए यह आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ देश की आर्थिक मज़बूती देने वाला है।

इसमें गांव, गरीब, किसानों और नौजवानों पर ज़ोर है। उन्होंने खुशी जताते हुए कि यह खेती को मज़बूत और किसानों की आय बढ़ाने वाला है जो देश की रीढ़ हैं। बजट के दिल में गांव और किसान हैं। इससे उनकी आय में इजाफा होगा। बजट में जो योजनाएं दिखाई गई हैं, उनसे देश की मंडियां और अधिक मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचना पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए नई योजनाएं हैं, जो उनकी आय को बढ़ाने में मददगार होंगी। कृषि उपकरण सस्ते होंगे। आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। गांव का विकास और युवाओं को रोजगार का विशेष ध्यान रखा गया है। नए बजट से किसानों में नई उम्मीदें जन्म लेंगी जो उनको आर्थिक रूप से मज़बूत बनाएगा।■

सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जा सकेगा। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जा रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में कमियों की भरपाई करते हुए युवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका से जुड़ी गतिविधियां चलाई जाएंगी।

2022 में शत–प्रतिशत 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे **'वित्तीय समावेश'** संभव होगा और 11 नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा और डाक घर के खाते से बैंक खाते के बीच धन का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए **'इंटर–ऑपरेबिलिटी और वित्तीय समावेशन'** की सुविधा उपलब्ध होगी।

देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता अनुकूल तरीके से देश के सभी हिस्सों तक डिजिटल बैंकिंग की पहुंच कायम हो।

नागरिकों के लिए उनकी विदेश यात्रा में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से 2022–23 में ईम्बडेड चिप तथा भविष्य की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए ई–पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि शहरी योजना और डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान विकसित करने और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, विभिन् क्षेत्रों में पांच मौजूदा शैक्षिक संस्थाओं को उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में नामित किया जाएगा। इन केंद्रों में से प्रत्येक को 250 करोड़ रुपये का इनडॉवमेंट फंड प्रदान किया जाएगा।

एनिमेशन, विजुअल इफैक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है। एक एवीजीसी संवर्धन कार्य बल सभी हितधारकों के साथ इसे साकार करने तथा हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण के लिए तौर–तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सामान्य रूप से दूर संचार और विशेष रूप से 5जी प्रौद्योगिकी, प्रगति और रोजगार के अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपेक्षित स्पैक्ट्रम नीलामियों को निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा

गांव गरीब किसान की आकांक्षाओं का हैं यह बजट- दिनेश शर्मा

डा0 दिनेश शर्मा ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को डिजिटल इण्डिया के भविष्य का दर्पण बताया और कहा कि इसमें देश की प्रगति के 25 सालों का ब्लू प्रिंट खींचा गया है। एमएसपी के मद में दी जाने वाली मदद भी बढ़ाई गई है। कृषि बजट गांव, गरीब, किसान सबकी आशाओं की पूर्ति करने वाला है। बजट में डिजिटल शिक्षा के प्रसार को लेकर की गई दो महत्वपूर्ण घोषणाएं शिक्षा को सुदूर एवं दुर्गम स्थानों तक पहुंचाने का क्रांतिकारी प्रयास है। महामारी जैसी परिस्थितियों में जब दुनिया ठहर जाती है तब पीएम ई–विद्या और डिजिटल विश्वविद्यालय जैसे प्रयास ज्ञान के प्रकाश से बच्चों और नौजवानों को रोशन करते रहेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चे महामारी जैसे दौर में शिक्षा से वंचित न रहें इसके लिए टीवी चैनलों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा के विस्तार के लिए 200 नये टीवी चैनल शुरू किये जाएंगे। देश की विभिन्न भाषाओं में आरंभ होने वाले इन चैनलों के आने से गरीब से गरीब बच्चा भी ज्ञानवान हो सकेगा। डिजिटल इण्डिया का डिजिटल विश्वविद्यालय उच्च और आधुनिक शिक्षा के प्रसार में मील का पत्थर साबित होगा। इसके जरिये अलग–अलग भाषाओं में दी जाने वाली गुणवत्तायुक्त शिक्षा राष्ट्र निर्माण के लिए सक्षम मानव साधन निर्माण में सहायक होगी। बजट युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान, किसानों के लिए आमदनी बढ़ानेवाला, ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को देनेवाला एवं उनके पिछड़ेपन को दूर कर आधुनिकता से जोड़नेवाला, सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को प्रस्तुत करने वाला है।■

2022–23 के भीतर 5जी मोबाइल सेवाओं के आरंभ को आसान बनाने के लिए 2022 में निष्पादित किया जाएगा। डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के भाग के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए शुरू की जाएगी।

रक्षा के मोर्चे पर हमारी सरकार निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्म निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजीगत खरीद बजट के 2021–22 में 58 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022–23 में घरेलू उद्योग के लिए 68 प्रतिशत तक धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के कार्यों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25 प्रतिशत हिस्से को उद्योग, स्टार्ट–अप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिया जाएगा।

उदीयमान अवसर के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि कृत्रिम मेधाविता, भू–स्थानिक प्रणालियों तथा ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसका इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स तथा फार्मास्युटिकल, हरित ऊर्जा और स्वच्छ आवागमन प्रणालियों में बड़े पैमाने पर यथासाध्य् विकास में सहायता करने तथा देश को आधुनिक बनाने की व्यापक संभावना है। यह युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करते हैं तथा भारतीय उद्योग जगत को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।

2030 तक संस्थापित सौर क्षमता के 280 जीडब्यू के महत्वाकांक्षी लक्ष्या के लिए घरेलू उत्पादन को सुविधा प्रदान करने के लिए सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पॉलीसिलिकॉन से पूर्णतः समेकित उत्पादन इकाइयों के लिए प्राथमिकता के साथ उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक निवेश को आगे बने रहने की जरूरत है और 2022–23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ाना भी जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए एक बार फिर केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। अभी यह चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें 35.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 2022–23 में 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह 2019–20 के व्यय से 2.2 गुना से भी अधिक बढ़ गया है और 2022–23 में यह परिव्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा। इस निवेश के साथ केंद्र सरकार का 'कारगर पूंजीगत व्यय' 2022–23

में अनुमानतः 10.68 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा, जो कि जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत होगा।

2022–23 में सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी बाजार उधारियों के सिलसिले में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे, जिनसे हरित अवसंरचना के लिए संसाधान जुटाए जाएंगे। इससे प्राप्तधन को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में सहायक हों।

सरकार ने ब्लॉक चेन और अन्य प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से डिजिटल रुपये की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2022–23 से होगी।

सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने 'राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए पूंजी निवेश योजना' के परिव्यय को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में 15,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा 2022–23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावा हैं। इस प्रकार के आवंटन का इस्तेमाल पीएम गतिशक्ति से जुड़े निवेशों और राज्यों की अन्य उत्पादक पूंजी निवेश में किया जाएगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2022–23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र में सुधार से संबंधित होंगे। इसकी शर्तों के बारे में 2021–22 में ही अवगत करा दिया गया है।

अपने बजट भाषण के भाग ए को समाप्त करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.9 प्रतिशत है, जबकि बजट अनुमान में यह 6.8 प्रतिशत है। 2022–23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.4 प्रतिशत है, जो कि राजकोषीय मजबूती के उस मार्ग के अनुरूप भी है। जिसकी पिछले वर्ष घोषणा की गई थी कि 2025–26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से निचले स्तर पर लाया जाएगा। 2022–23 के राजकोषीय घाटे के स्तार को निर्धारित करते समय उन्होंने मजबूती और टिकाऊपन के लिए सार्वजनिक निवेश के माध्यम से प्रगति के पोषण का आह्वान किया।

केंद्रीय बजट 2022–23 के प्रस्तावों का अभिप्रायः स्थिर और जानी–पहचानी कर प्रणाली, कर व्यीवस्था की हमारी घोषित नीति पर कायम रहते हुए और अधिक ऐसे सुधारों को लाना है जो एक विश्वसनीय कर व्यावस्था स्थापित करने की हमारी संकल्पना को आगे बढ़ा सके। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कर प्रणाली को और भी अधिक सरल बनाएगा, करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा।

प्रत्यक्ष कर के बारे में, यह बजट करदाताओं को त्रुटियों में सुधार के लिए दो वर्ष के भीतर अपडेट की हुई आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। यह दिव्यांगजनों के लिए भी कर राहत प्रदान करता है। यह बजट सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर और अधिभार में भी कमी लाने का प्रस्तीाव करता है। स्टार्ट–अप के लिए प्रोत्साहन के तौर पर, पात्र स्टार्ट–अप की शुरुआत की अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता लाने के उद्देश्य् से एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर की कटौती की सीमा को बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है। नई विनिर्माण इकाइयों को भी रियायती कर प्रणाली के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्चुअल संसाधनों के अंतरण से प्राप्त आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाएगा। बार–बार की अपील से बचने के लिए बजट में बेहतर मुकदमा प्रबंधन का प्रस्ताव किया गया है।

अप्रत्यक्ष कर के मामले में केन्द्रीय बजट के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सीमा–शुल्क प्रशासन को पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी से सक्षम बनाया जाएगा। यह पूंजीगत वस्तुओं एवं परियोजनागत आयातों में रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने और 7.5 प्रतिशत का साधारण प्रशुल्क प्रदान करता है। बजट में सीमा–शुल्कं छूट और प्रशुल्क सरलीकरण की समीक्षा का उल्लेख किया गया है और इसमें 350 से अधिक छूट प्रविष्टियों को धीरे–धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। सीमा–शुल्क दरों को घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को सुविधा प्रदान करने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से तैयार किया जाएगा। भारत में निर्मित कृषि क्षेत्र के लिए कार्यान्वयन

और उपकरणों पर छूट को युक्ति संगत बनाया जाएगा। स्टील स्क्रैप के लिए सीमा–शुल्का छूट को बढ़ाया जाएगा। मिश्रण रहित ईंधन अतिरिक्त अलग उत्पाद शुल्क को आकर्षित करेगा।

यह बजट अतिरिक्त कर के भुगतान पर अपडेटिड रिटर्न को फाइल करने के लिए कर प्रदाताओं को एक नए प्रावधान की अनुमति देता है। यह अपडेटिड रिटर्न संगत निर्धारण वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर दाखिल किया जा सकता है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस प्रस्ताव के साथ करदाताओं के भीतर भरोसा जगेगा, जिससे निर्धारित स्वयं उन आमदनी को घोषित कर पाएंगे जिसको पूर्व में उन्होंने अपने रिटर्न दाखिल करते समय नहीं दर्शाया था। यह स्वैच्छिक कर अनुपालन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता लाने के लिए इस बजट में सहकारी समितियों के लिए दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है। वित्तय मंत्री ने ऐसी सहकारी समितियों पर अधिभार की दर को भी मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है जिनकी कुल आमदनी एक करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक है।

वित्त मंत्री ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति के माता–पिता या अभिभावक ऐसे व्यंक्ति के लिए बीमा स्कीम ले सकते हैं। वर्तमान कानून में माता–पिता या अभिभावक के लिए केवल तभी कटौती करने का प्रावधान है जब दिव्यांग व्येक्ति के लिए अभिदाता यानी माता–पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी की सुविधा उपलब्ध हो। इस बजट में माता–पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान भी यानी माता–पिता/अभिभावकों के साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है।

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) टीयर–1 में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14 प्रतिशत का योगदान करती है। इसे कर्मचारी के आय की गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है। हालांकि, राज्यं सरकार के कर्मचारियों के मामले में ऐसे कटौती वेतन के 10 प्रतिशत की सीमा तक ही स्वीकृत की गई है। बजट में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के प्रति समान व्यवहार करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को 10 प्रतिषत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

31.03.2022 से पहले स्थापित पात्र स्टार्ट–अप को निगमन से दस वर्षों में से तीन क्रमिक वर्षों के लिए कर प्रोत्सारहन दिया गया था। कोविड महामारी को देखते हुए बजट में कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्ट–अप के निगमन की अवधि और एक वर्ष यानी 31.03.2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।

घरेलू कंपनियों के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी परिवेश कायम करने के लिए सरकार द्वारा नव–निगमित घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत कर की रियायती कर व्यवस्था लागू की गई थी। केन्द्रीय बजट में धारा 115 (क) के अंतर्गत विनिर्माण या उत्पादन के आरंभ करने की अंतिम तिथि को एक वर्ष यानी 31 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक रहने का प्रस्ताव दिया गया है।

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण बढ़ोत्तरी हुई है। इन अंतरणों की परिमाण और बारम्बारिता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए किए विशिष्ट कर व्यवस्था का उपबंध किया जाए। इसके अनुरूप वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए बजट में कर उपबंध का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा। अधिग्रहण की लागत के सिवाय ऐसी आमदनी का परिकलन करते समय किसी व्यैय या भत्ते के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्ता, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई हानि किसी अन्य आमदनी के प्रति समंजित नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अंतरण विवरणों को दर्ज करने के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक मौद्रिक सीमा से अधिक, ऐसे प्रतिफल पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस लेने के लिए भी प्रस्ताव किया गया है।

त्वरित मुकदमा प्रबंधन की नीति आगे बढ़ाते हुए बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि किसी निर्धारित के मामले में कानून का एक प्रश्न, किसी भी मामले में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कानून के प्रश्न के सदृश है तो विभाग द्वारा इस निर्धारित के मामले में आगे अपील

दायर करना तब तक के लिए अस्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि वैसे कानून के प्रश्न पर अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय न ले लिया जाए।

बजट में यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि अपतटीय व्युत्पन्नी लिखितों या किसी अपतटीय बैंकिंग यूनिट द्वारा काउंटर पर निर्गत व्यैुत्पन्नियों से अनिवासी को हुई आमदनी, रॉयल्टी से हुई आमदनी और जहाज को पट्टे पर देने के व्याज और आईएफएससी में पोर्टफोलियों मैनेजमेंट सेवाओं से प्राप्त आमदनी, विशिष्ट शर्तों के अधीन कर से मुक्त होगी।

बजट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कारोबार व्यय के तौर पर आय और लाभों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कर का भुगतान न करने वाले लोगों के मामले में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि तलाशी या छानबीन अभियान के दौरान पता चली किसी भी अघोषित आय को किसी भी प्रकार हानि या नुकसान के रूप में स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

बजट के मुताबित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के सीमा–शुल्क प्रशासन में सुधारों को कार्यान्वित किया जायेगा और यह पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त होंगे तथा जोखिम आधारित जांच के साथ अत्यधिक सुविधा पर ध्यान देने के साथ ये सीमा–शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल पर संचालित होंगे। यह सुधार 30 सितम्बर, 2022 से क्रियान्वित होंगे।

पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनागत आयातों में रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने के लिए और 7.5 प्रतिशत का साधारण प्रशुल्क अधिरोपित करने का प्रस्ताव है। बजट में कहा गया है कि उन उन्नत मशीनरियों पर कतिपय छूट बनी रहेगी जिनका देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है। निविष्टियों, जैसे कि विशेषीकृत कॉस्टिंग्स, बॉल स्क्रू और लीनियर मोशन गाइड पर कुछ छूट देने का चलन शुरू किया जा रहा है ताकि पूंजीगत वस्तुगओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

बजट में 350 से अधिक छूट प्रविष्टियों को धीरे–धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें कतिपय कृषि उत्पााद, रसायन, वस्त्री, मेडिकल उपकरण और ड्रग्स एवं औषधियां शामिल हैं जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। आगे, एक सरलीकरण उपाय के रूप में कई रियायती दरें, इन्हें विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से विहित करने के बजाय, सीमा शुल्क प्रशुल्क अनुसूची में ही समाविष्ट किया जा रहा है।

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काटे एवं तराशे गए हीरे एवं रत्न–पत्थरों पर सीमा शुल्क लगेगा। ई–कॉमर्स के माध्याम से आभूषण के निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क इस साल के जून तक क्रियान्वित किया जाएगा। अल्प –मूल्यांकित इंटिमेशन आभूषण पर सीमा शुल्क को इस तरह निर्धारित किया जा रहा है कि इसके निर्यात पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क अदा किया जाए।

बजट में कुछ अत्यंत महत्व पूर्ण रसायन, नामतः मेथेनॉल, एसीटिक एसिड और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए हैवी फीड स्टॉक पर सीमाशुल्क कम किया जा रहा है, जबकि सोडियम साइनाइड पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है।

बजट में छातों पर शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। छातों के कलपुर्जों पर छूट वापस ली जा रही है। कृषि क्षेत्र के लिए भी उन औजारों और साधनों पर छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है जो भारत में निर्मित की जाती है। पिछले वर्ष इस्पात स्क्रैप को दी गई सीमा शुल्क छूट और एक वर्ष के लिए दी जा रही है ताकि एमएसएमई के द्वितीयक इस्पा्त उत्पादों, मिश्रित इस्पात की छड और हाई–स्पीड स्टीएल पर कतिपय डम्पिंग रोधी और सीवीडी को धातुओं की मौजूदा उच्च कीमत को देखते हुए व्यापक लोक हित में समाप्त किया जा रहा है।

बजट में निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए वस्तुओं जैसे कि सजावटी सामान, ट्रिमिंग, फास्नर्स, बटन, जिपर, लाइनिंग सामग्री, विनिर्दिष्ट चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्सं और पैकेजिंग बॉक्स, जिनकी हस्त शिल्प, कपड़े और धर्म परिधानों, लेदर फुटवियर और अन्य, वस्तुओं के वास्तविक निर्यातकों को जरूरत पड़ सकती है, पर छूट दी जा रही है।

बजट में कहा गया है कि ईंधन का सम्मिश्रण सरकार की प्राथमिकता है। ईंधन के सम्मिश्रण के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, असम्मिश्रित ईंधन पर 1 अक्तूबर, 2022 से दो रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा।■

नए संकल्पों की सिद्धि का समय है : नरेन्द्र मोदी

केंद्रीय बजट 2022–23 के परिप्रेक्ष्य में देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित वर्चुअल संवाद कार्यक्रम "आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था" को संबोधित किया और इस बार के बजट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही, इस प्रो–पीपल और प्रोग्रेसिव बजट के विभिन्न आयामों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव श्री बी. एल. संतोष जी, पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, केंद्र सरकार में मंत्री तथा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं नेता डॉ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली और कई अन्य जगहों से वर्चुअली जुड़े। देश भर में लगभग 1800 स्थानों से राज्य, जिला और मंडल स्तर से भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप–मुख्यमंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लाखों पार्टी कार्यकर्ता जुड़े।

'बजट 2022-23' 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था'

7-8 साल पहले भारत की जीडीपी 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2 लाख 30 हजार करोड़ के आसपास की है। वर्ष 2013-14 में सार्वजानिक निवेश सिर्फ 1 लाख 87 हजार करोड़ था। इस बजट में ये 7 लाख 50 हजार करोड़ रुपए है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने इस तरह के संवाद कार्यक्रम की रचना की और मुझे बजट पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। कल निर्मला सीतारमण जी ने हुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे ढंग से बजट के कुछ पहलुओं को हमारे सामने रखा है।

आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था

श्री मोदी ने कहा कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया बदल गई, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है। इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से देश लड़ रहा है। कोरोना का ये कालखंड पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं, वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। ये भारत के लिए नए सिरे से तैयारी का, नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और उस आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सात वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनीं, पहले की जिन नीतियों में सुधार हुआ, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। 7–8 साल पहले भारत की जीडीपी 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2 लाख 30 हजार करोड़ के आसपास की है। जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाता है। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थाई समाधानों से जोड़ने पर है।

केंद्र सरकार के प्रयासों से आज देश में लगभग 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। इसमें से लगभग 5 करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्ष में दिए गए हैं। केन-बेतवा को ल्लक करने के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे यूपी और एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर भी बदलने वाली है। अब बुंदेलखंड के खेतों में और हरियाली आएगी, घरों में पर्याप्त पीने का पानी आएगा, खेतों में पानी आएगा।

श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में करीब–करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। इसमें से करीब–करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्ष में दिए गए हैं। अब बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इस पर 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। विशेष रूप से केन–बेतवा को लिंक करने के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे यूपी और एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर भी बदलने वाली है। अब बुंदेलखंड के खेतों में और हरियाली आएगी, घरों में पर्याप्त पीने का पानी आएगा, खेतों में पानी आएगा।

मोदी जी ने कहा कि भारत जैसे देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा रहे, ये ठीक नहीं था। इसलिए हमने

आकांक्षी जिला अभियान शुरू किया था। इन जिलों में गरीब की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए, बिजली–पानी के लिए जो काम हुए, उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। सीमा पर मौजूद गांवों के विकास के बारे में नए सिरे से सोचा गया है। ऐसे गावों में हर प्रकार की सुविधा हो, बिजली–पानी–सड़क का इंतजाम हो, इसके लिए बजट में विशेष वाइब्रेंट विलेज प्रोगाम का ऐलान किया गया है। राष्ट्र रक्षा से जुड़े एक और बड़े अभियान 'पर्वतमाला परियोजना' की बजट में घोषणा की गई है। ये हिमालय के क्षेत्रों में आधुनिक कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने वाली है।

श्री मोदी ने कहा कि देश की कृषि को टेक्नॉलॉजी आधारित और कैमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। बीते बजट में हमने किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधा सुनिश्चित की, अब किसान ड्रोन किसान का नया साथी बनने वाला है। अब हम नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। ये कॉरिडोर 2500 किलोमीटर का होगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मां गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा।

माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल जो लाखों करोड़ रुपए हम खाद्य तेल खरीदने के लिए विदेश भेजते हैं, वह देश के किसानों को ही मिले, इसके लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का एक बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है जिसके माध्यम से खेत में ही सोलर पैनल लगाने के लिए मदद दी जा रही है। एमएसपी को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें फैलाई गई लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। सिर्फ धान की ही बात करें तो इस सीज़न में किसानों को एमएसपी के रूप में डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है।

श्री मोदी ने कहा कि भाजपा युवा आकांक्षाओं और युवा सपनों को समझती है। ये इस बजट में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। इस बजट में स्टार्ट अप्स के लिए टैक्स बेनिफिट को आगे बढ़ाया गया है। अब पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांस्फर की सुविधा मिल पाएगी। अभी देश में डेढ़ लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें से अधिकतर गांवों में हैं। पोस्ट ऑफिस में जिनके सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट हैं, उनको भी अब अपनी किश्त

भाजपा युवा आकांक्षाओं और युवा सपनों को समझती है। इस बजट में स्टार्ट अप्स के लिए टैक्स बेनिफिट को आगे बढ़ाया गया है। अब पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंलकग, इंटरनेट बैंलकग, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांस्फर की सुविधा मिल पाएगी।

जमा करने पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सीधे अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएंगे। अब पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांस्फर की सुविधा मिल पाएगी।

आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सस्ता और तेज़ इंटरनेट भारत की पहचान बन चुका है। बहुत जल्द सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पूरी होगी। 5ळ सर्विस की लॉन्चिंग भारत में ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को एक अलग ही आयाम देने वाली है। आज देश में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (AVGC) सेक्टर भी तेज़ी से विकास कर रहा है। भारत मोबाइल गेमिंग को लेकर दुनिया के टॉप 5 मार्केट्स में से एक है। इस सेक्टर में "क्रियेट इन इंडिया" और "ब्रांड इंडिया" को सशक्त करने का भरपूर पोटेंशियल है। भारत को ग्लोबल गेम डेवलपर्स और गेमिंग सर्विस का हब बनाने के लिए इस बजट में एक टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई है।

श्री मोदी ने कहा कि आज के अखबारों में डिजिटल करेंसी की भी काफी चर्चा है। इससे डिजिटल इकॉनॉमी को बहुत बल मिलेगा। ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी है उसका ही डिजिटल स्वरूप होगा और इसे आरबीआई द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इसको फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकेगा। कोरोना काल में हमने छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की थी। एसबीआई के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस योजना से डेडम सेक्टर में लगभग डेढ़ करोड़ नौकरियां सुरक्षित हुई हैं और करीब 6 करोड़ लोगों की जीविका सुरक्षित हुई है।

माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार बजट में एक बात जो सबसे खास, और सबसे अलग है तो वो है – पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये कितना बड़ा कदम है और इसका असर कितना बड़ा होगा, इस बात का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि वर्ष 2013–14 में सार्वजानिक निवेश सिर्फ 1 लाख 87 हजार करोड़ था। इस बजट में ये 7 लाख 50 हजार करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में 90 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवेज थे। ये 90 हजार किलोमीटर हाइवे पिछले 70 सालों में बने थे। हमने पिछले 7 सालों में ही 50 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवेज बनाए हैं। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत देश में नए हाइवे और बनाएँगे।

2014 में देश में 90 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवेज थे। ये 90 हजार किलोमीटर हाइवे पिछले 70 सालों में बने थे। हमने पिछले 7 सालों में ही 50 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवेज बनाए हैं। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत देश में नए हाइवे और बनाएँगे।

इन 7 सालों में हमने 25 हजार गैर-जरूरी अनुपालनों को खत्म किया है। 15 सौ गैर-जरूरी और पुराने क़ानूनों को भी खत्म किया गया है। इसी भरोसे की बुनियाद पर सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0' अभियान भी शुरू करने जा रही है।

श्री मोदी ने कहा कि देश में चार जगहों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक फेसिलिटीज के लिए 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। इससे उद्योगों, व्यापार के लिए किसी भी चीज के लाने ले जाने में लगने वाला समय कम होगा, भारत से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन 7 सालों में हमने 25 हजार गैर–जरूरी अनुपालनों को खत्म किया है। 15 सौ गैर–जरूरी और पुराने क़ानूनों को भी खत्म किया गया है। इसी भरोसे की बुनियाद पर सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0' अभियान भी शुरू करने जा रही है। ■

सपा, बसपा की सरकार में माफिया राज था, आज कानून का राज है : नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश के उप–मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नामांकन के बाद मंझनपुर (कौशांबी) के फायर ब्रिगेड मैदान में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के चुनावी जन–सभा को संबोधित किया और विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश के विकास की इस लड़ाई में न केवल केशव प्रसाद मौर्य जी को बल्कि भाजपा को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और एक बार पुनः 300 से अधिक सीटों पर विजय के साथ एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार बनेगी।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और अपना दल (सोने लाल) की अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल भी थीं। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी सिराथू विधानसभा से जीत हासिल कर क्षेत्र में जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नामांकन के पश्चात् फायर ब्रिगेड मैदान जाते वक्त पूरा काफिला एक भव्य रोड शो में तब्दील हो गया। इस भव्य रोड शो में स्थानीय जनता का उत्साह देखते ही बनता था। पूरा क्षेत्र भाजपा के झंडे से पट गया था और भारत माता की जय के नारे हर दिशा में गुंजायमान हो रहे थे।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा और संगठन आधारित पार्टी है जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां है। कोई परिवारवाद में फंसा हुआ है तो कोई भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। सपा, बसपा और कांग्रेस ने संसद में धारा 370 को खत्म करने का विरोध किया था। इन्होंने अयोध्या में भगवान् श्रीराम के भव्य मंदिर का विरोध किया था। इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं जिन्होंने धारा 370 को धाराशायी किया, ट्रिपल तलाक को खत्म किया और अयोध्या में भगवान् श्रीराम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया। आज सपा, बसपा और कांग्रेस वाले मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, कोई घंटी बजा रहा है तो कोई तिलक लगा रहा है लेकिन याद रखना, ये वहीं हैं जिन्होंने भगवान् श्रीराम के भक्तों पर गोलियां चलाई थी, ये वहीं हैं जिन्होंने भगवान् श्रीराम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। अब भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण को कोई रोक नहीं सकता, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर–कमलों से भव्य मंदिर का शिलान्यास हो चुका है।

सपा, बसपा और कांग्रेस जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां है।

श्री नड्डा ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, अध्यात्म सर्किट, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट बना कर इसे धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सपा, बसपा और कांग्रेस ने लोगों की आस्था पर चोट की है जबकि भारतीय जनता

लाभ मिल रहा है, किसान मानधन योजना के तहत किसानों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था हुई है और डीएपी खाद पर प्रति बोरी 12,00 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस बार रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीद भी हुई है और भुगतान भी। गन्ना किसानों को यूपी में सपा–बसपा सरकार के समय किये गए कुल भुगतान से भी ज्यादा लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा भुगतान किया गया है। सपा–बसपा की सरकार में लगभग 20 से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई थी लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई बल्कि तीन नई मिलें खुली हैं और 20 चीनी मिलों की क्षमता को विस्तारित किया गया है।

पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज लेकर चली है।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गरीब कल्याण का लक्ष्य लेकर श्री नरेन्द्र मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास' की अवधारणा पर काम कर रही है। आज तक गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता किसी ने नहीं की जबकि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने न केवल दवाइयों के दाम कम किये बल्कि देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया। उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों लोगों को इस योजना से फायदा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान और खुले में शौच से मुक्ति का जो अभियान छेड़ा था, उससे महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला है। उत्तर प्रदेश में लगभग ढाई करोड़ शौचालय बने। सरकार में लगभग 42 लाख गरीबों के घर बने और घर में बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन का प्रबंध किया गया। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से घर–घर बिजली पहुंची।

नरेन्द्र मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास' की अवधारणा

किसानों का हितैषी होने का दंभ भरने का दावा आज कल के कई नेता करते हैं, मुट्ठी में अनाज लेकर घूमते हैं लेकिन किसानों के उत्थान के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया, वह आज तक किसी ने भी नहीं किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने केवल किसान सम्मान निधि में ही अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंचा दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश में लगभग 86 लाख किसानों के लगभग 36,000 रुपये का कृषि ऋण माफ़ हुआ है। यूपी में भी ढाई करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। आज करोड़ों किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल रहा है, स्वायल हेल्थ कार्ड का

श्री नड्डा ने कहा कि हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत साधारण परिवार से निकल कर आये हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उनके नेतृत्व में सिराथू का विकास ही विकास होगा। सिराथू में 50 बेड का अस्पताल बना रहा है, ऑक्सीजन प्लांट लगा है। रेलवे और सड़कों का निर्माण हो रहा है। भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी गठबंधन का लक्ष्य है विकास जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस का लक्ष्य है भ्रष्टाचार, अपराधियों को संरक्षण और केवल अपने–अपने परिवार का भला करना। एक तरफ भाजपा गठबंधन है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का घर बनवाती है जबकि दूसरी तरफ वे लोग हैं जो पहले गरीबों के घर पर अवैध कब्जा जमा लेते थे। सपा–बसपा की सरकार में माफिया राज था, आज कानून का राज है। सपा–बसपा की सरकार में अपहरण उद्योग चल रहा था, आज अपहरण करने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। गुंडागर्दी और सपा, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते आतंकियों को जेल से छुड़ाने की कोशिश की थी। वो तो भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि उन्होंने अखिलेश यादव की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। जाँच के आधार पर जब सुनवाई हुई और फैसला आया तो कई आतंकवादियों को फांसी और उम्रकैद की सजा हुई। गरीब जनता को लूटने वालों को आराम दीजिये और जन–जन के विकास के लिए समर्पित भाव से काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक बार पुनः सेवा करने का मौक़ा दीजिये। ■

‘डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को दिलाई गुंडाराज से मुक्ति’

सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में प्रदेश को सत्ता के संरक्षण में माफियाओं, गुंडों ने जकड़ लिया था। केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन भाजपा सरकार ने प्रदेश को माफिया व गुंडाराज से मुक्ति दिलाई है। सुरक्षा का माहौल बना तो बेटिया स्कूल जा रही हैं। बहन, माताएं सम्मान से जी रही हैं। सुरक्षा के वातावरण से प्रदेश में निवेश और निवेश से रोजगार के अवसर तेजी से आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में दो तरह का पलायन होता था। माफिया राज होने से व्यापारियों का और रोजगार के अवसर न मिलने से युवा प्रतिभाओं का। भाजपा सरकार में दोनों तरह का पलायन रुका है। व्यापारियों को पलायन के लिए मजबूर करने वाले गुंडे व पेशेवर माफिया आज कानून के भय से खुद पलायन कर गए हैं। जबकि व्यापारी और युवा यही रहकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

‘यूपी में अब नहीं होती भूख से कोई मौत’

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 के पहले भूख से गरीबों की मौत आम बात मानी जाती थी। कुशीनगर और महराजगंज के मुसहर भूख से मरने के लिए अभिशप्त थे। जनवरी 2017 में भी कुशीनगर में मुसहरों की भूख से मौत हुई थी। अपना संसदीय क्षेत्र न होने के बावजूद मैंने वहां जाकर भूख से तड़प रहे लोगों की पीड़ा को महसूस किया था, उनके लिए आवाज उठाई थी। आज भाजपा सरकार ने उनके कल्याण की ऐसी व्यवस्था कर दी है कि न सिर्फ मुसहर बल्कि पूरे यूपी में किसी की मौत भूख के कारण नहीं होती है। सीएम ने कहा विगत एक हजार सालों में जितनी भी महामारियां आईं, उनमें बीमारी से कई गुना अधिक मौतें भूख के चलते हुईं। पर, सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सफल प्रबंधन से यूपी में किसी की भी जान भूख के कारण नहीं गई। डबल इंजन सरकार प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राशन का डबल डोज दे रही है।

‘आत्महत्या करते थे किसान, आज उनके कल्याण का रचा इतिहास’

सीएम योगी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि 2004 से 2014 के बीच देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हित मे किए गए कार्यों से इस पर रोक लगी है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद भी प्रदेश की सरकार किसान हित वाली केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करती थी। इसके चलते किसान खेतीबाड़ी से भाग रहा था। बिचौलिए एमएसपी का लाभ लेते थे जबकि किसान वंचित रह जाता था। कई साल तक गन्ना किसानों को उनके मूल्य का भुगतान नहीं किया गया। अन्नदाता सिंचाई के लिए परेशान रहता था। सिंचाई की परियोजनाएं दशकों से लंबित थी। 2017 के पूर्व पूरे यूपी में बिजली न मिलने से भी सिंचाई प्रभावित होती थी। आज सबको पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली

मिल रही है। प्रदेश सरकार ने 1 लाख 21 हजार अतिरिक्त मजरों का विद्युतीकरण कराया है। दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूर्वांचल के 9 जिलों को जोड़ रही है तो बाणसागर परियोजना मिर्जापुर–प्रयागराज को तथा अर्जुन बांध परियोजना बांदा, महोबा, हमीरपुर जैसे बुंदेलखंडी जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार ने 30 वर्षों से लंबित सिंचाई की 18 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया है। इससे 21 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचन क्षमता का विस्तार हुआ है। किसानों के हित के लिए सरकार के कार्यों की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान अपने खेतों में ही गन्ने पर आग लगा देता था। पर भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान यह नौबत नहीं आई । जब तक एक भी खूंट गन्ना किसान के खेत में रहा तब तक हमने सभी 119 मिले चलाई। भाजपा सरकार ने 1.57 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया है। पूर्व की सरकारों ने 29 चीनी मिलों को या तो बंद कर दिया था यह बेच दिया था। हमने बंद मिलो को चलाया, मुंडेरवा व पिपराइच में नई चीनी मिलें खोली तो आजमगढ़ समेत अन्य मिलों की क्षमता का विस्तारीकरण किया। आज उत्तर प्रदेश में गन्ने के रस से सीधे एथेनाल बनाया जाता है। एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर वन है। सरकार ने कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी इस वर्ष 62 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया है जबकि गत वर्ष 66 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई थी।

सीएम ने कहा कि किसानों के हित मे उनकी सरकार ने पहला निर्णय ही 86 लाख किसानों की 36 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी का किया। प्रदेश में 2.54 करोड़ किसानों को 42 हजार करोड़ रुपये की पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि मिली है।

'गरीब कल्याण को समर्पित है सरकार'

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सपा सरकार ने बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं व दिव्यांगों का पेंशन बंद कर अपने कैडर के कार्यकर्ताओं को दे दिया था। हमारी सरकार आई तो पूछा कि समाजवादी पेंशन पाने वालों का समाज मे योगदान क्या है। यह स्पष्ट कर दिया कि थानों की दलाली करने वालों, तहसीलों को गिरवी रखने वालों को गरीबों का निवाला नहीं खाने दिया जाएगा।

'सैफई में लुटाया जाता था प्रदेश का खजाना'

सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार में प्रदेश का खजाना सैफई में महोत्सव के नाम पर लुटाया जाता था। अब यूपी में स्थापना दिवस का समारोह विकास की गाथा प्रस्तुत करता है। अयोध्या के दीपोत्सव, वृंदावन–बरसाना के रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली और प्रयागराज का भव्य–दिव्य कुम्भ प्रदेश की पहचान बन पर्यटन और विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में रोजगार की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बीते पांच साल में पांच लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं जबकि सपा, बसपा की सरकारों में दस साल में मिलकर सिर्फ 1.90 लाख सरकारी नौकरी दी थी। वह भी पैसे के लेनदेन से। सुरक्षा का माहौल बनने से निजी क्षेत्र में व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए हैं। ■

भाजपा उत्तर प्रदेश में पुनः इतिहास रचने जा रही है : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी ने गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन में शामिल हुए और कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखी है। नॉमिनेशन से पहले आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गोरखपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और जनता से भाजपा के लिए आशीर्वाद माँगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एवं यूपी चुनाव प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ संजय निषाद, अपना दल (सोने लाल) से श्री आशीष पटेल, श्री शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा सांसद श्री रवि किशन शुक्ला, श्री कमलेश पासवान और गोरखपुर से वर्तमान विधायक डॉ राधामोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे। कार्यकर्ता सम्मेलन के पश्चात् श्री शाह ने श्री श्री गोरक्षपीठ धाम में पूजा–अर्चना की और उत्तर–प्रदेश में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा की मंगलकामना की।

श्री शाह ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार इतिहास रचने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 – तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नामांकन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर भाजपा उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर जीत के संकल्प के साथ आगे बढ़ चुकी है। गोरखपुर की धरती भी पवित्र भूमि है। यह महायोगी भगवान् शिव का अवतार माने जाने वाले महान योगी गोरखनाथ की भूमि है। साथ ही, यह कबीरदास, महात्मा बुद्ध और भगवान् महावीर की भी कर्मभूमि है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार इतिहास रचने जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नामांकन के साथ ही भाजपा उत्तर प्रदेश में ३०० से अधिक सीटों पर जीत की राह पर आगे बढ़ चली है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराया है। आज अपराधी और माफिया या तो जेल में दिखाई देते है, या उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर या फिर अखिलेश यादव की प्रत्याशियों की सूची में। सपा–बसपा की सरकार में हर जनपद में एक माफिया और एक बाहुबली का राज होता था लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में माफिया खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 25 साल बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज प्रतिस्थापित हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी संसद में उत्तर प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका स्पष्ट मानना रहा है कि जब तक उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होता, तब तक देश के विकास की कल्पना असंभव है।

श्री शाह ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लगभग 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का अद्भुत कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 15 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत साढ़े सात वर्षों में देश के हर

गरीब के लिए घर उपलब्ध कराया है और उस घर में बिजली, गैस, पानी और शौचालय का प्रबंध किया है। साथ ही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कवर दिया है। कोरोना काल में देश के सभी नागरिकों का मुफ्त में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की हर कल्याणकारी योजना को योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की जमीन पर बहुत ही अच्छे से उतारा है। उत्तर प्रदेश केंद्र की हर योजना को जमीन पर लागू करने में एक से पांच के बीच है। लगभग 45 योजनाओं में तो उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उज्जवला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 1.73 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए, लगभग 42 लाख गरीबों के घर बने, लगभग 1.82 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई और सर्वाधिक कोविड वैक्सीन उत्तर प्रदेश में ही लगाए गए। कोरोना काल में दो वर्षों में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार देश के लगभग 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है। उत्तर प्रदेश में भी 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। योगी जी ने केंद्र सरकार की योजना में राज्य सरकार की ओर से भी योगदान देते हुए इसमें दाल और तेल भी जोड़ दिया है।

श्री श्री गोरखनाथ मंदिर की तीन-तीन पीढ़ियों ने इस शहर को न केवल सलामती देने का का काम किया बल्कि संवारने का भी काम किया है। मेरा योगी आदित्यनाथ जी के गुरु योगी अवैद्यनाथ जी से काफी निकट का संबंध रहा है। उन्होंने समग्र समाज को एक साथ रख कर सबके विकास के लिए कार्य किया।

विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया हुआ है जिसके कारण जन सभाएं सीमित हैं, यह विपक्ष के लिए अच्छा ही है क्योंकि उन्हें जनता के बीच जाना नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा एक बार पुनः 300 से अधिक सीटों पर जीत के साथ एक बार फिर इतिहास लिखने जा रही है।

सपा की अखिलेश यादव सरकार में माफिया और अपराधी खुले आम घूमते थे, आज आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जेल की सलाखों के पीछे है। उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सालों बाद इनके आतंक से मुक्ति मिली है।

श्री शाह ने कहा कि सपा की अखिलेश यादव सरकार में माफिया और अपराधी खुले आम घूमते थे, आज आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जेल की सलाखों के पीछे है। उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सालों बाद इनके आतंक से मुक्ति मिली है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश और बिहार माफियाओं के छुपने का स्थान माने जाते थे, आज यहाँ विकास की कहानी लिखी जा रही है। गोरखपुर ने विकास को एक नई गति दी है। हमारे लिए ळवतंीचनत (गोरखपुर) का मतलब है – '**G**' से गंगा एक्सप्रेस, '**O**' से 'ऑर्गनिक कृषि', '**R**' से 'रोड', '**A**' से 'एम्स', '**KH**' से 'खाद', '**PU**' से 'पूर्वांचल एक्सप्रेस' और '**R**' से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। एक समय गोरखपुर जापानी बुखार के गिरफ्त में था, आज इसमें 90 प्रतिशत की कमी आई है।

श्री गोरखनाथ मंदिर की तीन–तीन पीढ़ियों ने इस शहर को न केवल सलामती देने का का काम किया बल्कि संवारने का भी काम किया है। मेरा योगी आदित्यनाथ जी के गुरु योगी अवैद्यनाथ जी से काफी निकट का संबंध रहा है। उन्होंने समग्र समाज को एक साथ रख कर सबके विकास के लिए कार्य किया। योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर से पांच बार सांसद रहे हैं, वे विगत पांच वर्षों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं जब–जब गोरखपुर आता हूँ तो गोरखपुर के सौंदर्य और विकास की एक अलग ही छटा देखता हूँ।

श्री शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का कार्य किया है। डबल इंजन की भाजपा सरकार ही उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर गतिशील बनाए रख सकती है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और कानून–व्यवस्था को सुदृढ़ कर माताओं–बहनों का सम्मान बचा कर गौरव से जीने का अवसर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। ■

कैबिनेटने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 19 जनवरी को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (आईआरईडीए) में नकदी देकर इक्विटी शेयर खरीदने के जरिये 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने को मंजूरी दे दी। नकदी देकर इक्विटी शेयर जारी करने से साल भर में लगभग 10,200 रोजगारों का सृजन होगा तथा लगभग 7.49 मिलियन टन सीओ2 / प्रतिवर्ष के बराबर कार्बन डाई–ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आयेगी।

भारत सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपये के मद्देनजर नकदी देकर अतिरिक्त शेयर खरीदने से आईआरईडीए की निम्नलिखित क्षमता हो जायेगी:

- अक्षय ऊर्जा सेक्टर को लगभग 12,000 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा, जिससे अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र की ऋण आवश्यकता पूरी होगी, जो लगभग 3,500–4,000 मेगावॉट की अतिरिक्त क्षमता से सम्बंधित है।
- उसकी निवल संपत्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो अतिरिक्त आरई वित्तपोषण के लिये सहायक होगी। इस तरह सरकार द्वारा निर्धारित आरई लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतर योगदान हो सकेगा। ■

बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने सुपरसोनिक गति से उड़ान भरी और परीक्षण के लिए निर्धारित सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। यह मिसाइल उन्नत स्वदेशी तकनीकों से लैस है और बढ़ी हु दक्षता तथा बेहतर प्रदर्शन के लिए इसने एक संशोधित इष्टतम प्रक्षेप पथ का ही अनुसरण किया

स्वदेश में निर्मित और बेहतर क्षमता प्रदर्शन के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक परीक्षण 20 जनवरी को ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह परीक्षण ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की टीमों के साथ मिलकर किया गया था। इस मिसाइल परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए अनुमानित प्रक्षेप पथ का अनुसरण किया। परीक्षण की सफलता ने ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख मील का पत्थर स्थापित किया है। अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए अत्यधिक कुशल इस मिसाइल ने सुपरसोनिक गति से उड़ान भरी और परीक्षण के लिए निर्धारित सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। यह मिसाइल उन्नत स्वदेशी तकनीकों से लैस है और बढ़ी हुई दक्षता तथा बेहतर प्रदर्शन के लिए इसने एक संशोधित इष्टतम प्रक्षेप पथ का ही अनुसरण किया। संशोधित नियंत्रण प्रणाली वाली ब्रह्मोस मिसाइल को बेहतर क्षमता हासिल करने के लिए और ज्यादा उन्नत बनाया गया है। इस परीक्षण की निगरानी पूर्वी तट पर और डाउन रेंज जहाजों पर तैनात टेलीमेट्री, रडार तथा इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन के सभी सेंसरों द्वारा की गई थी।

डीआरडीओ और रूस की एनपीओएम संस्था की टीमों ने परीक्षण में हिस्सा लिया। डीआरडीओ तथा रूस की एनपीओएम के बीच संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस समुद्र में और जमीन के ऊपर निर्धारित लक्ष्यों पर इसकी प्रभावशीलता तथा घातक क्षमता को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली एवं अनेक दक्षताओं से युक्त ब्रह्मोस को लगातार उन्नत बना रहा है। ब्रह्मोस एक शक्तिशाली मिसाइल हथियार प्रणाली है, जिसे पहले ही सशस्त्र बलों में शामिल किया जा चुका है।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए ब्रह्मोस, डीआरडीओ की टीमों और रक्षा उद्योग जगत को बधाई दी।■

कैबिनेटने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन साल बढ़ाने की दी मंजूरी

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2022 के बाद 3 वर्ष तक बढ़ाने से मुख्य रूप से देश के सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने वाले चिन्हित लोग लाभार्थी होंगे। 31 दिसंबर, 2021 को एम.एस. अधिनियम सर्वेक्षण के तहत चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या 58,098 है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जनवरी को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को 31 मार्च, 2022 से आगे तीन साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी। तीन साल के लिए विस्तार का कुल व्यय लगभग 43.68 करोड़ रुपये होगा।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2022 के बाद 3 वर्ष तक बढ़ाने से मुख्य रूप से देश के सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने वाले चिन्हित लोग लाभार्थी होंगे। 31 दिसंबर, 2021 को एम.एस. अधिनियम सर्वेक्षण के तहत चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या 58,098 है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार शुरू में 31 मार्च, 1997 तक की अवधि के लिए की गई थी। बाद में अधिनियम की वैधता को शुरू में 31 मार्च, 2002 तक और उसके बाद 29 फरवरी, 2004 तक बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) अधिनियम 29 फरवरी, 2004 से प्रभावी नहीं रहा। उसके बाद एनसीएसके के कार्यकाल को समय–समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर–सांविधिक संस्था के रूप में बढ़ाया गया है। वर्तमान आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2022 तक है।■

वैचारिकी

सिद्धांत और नीतियां

पं. दीनदयाल उपाध्याय

भारत प्रजातंत्रवादी देश है। हम रूस, चीन या दूसरे कम्युनिस्ट देशों की भांति एक अधिनायकवादी पद्धति नहीं अपना सकते। अतः हमें वही योजना बनानी होगी, जिसका कार्यान्वयन लोकतंत्रीय पद्धति से हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पूर्ण सुविचारित, विवरणमूलक योजना बनानी चाहिए, किंतु निजी क्षेत्र में मोटे–मोटे लक्ष्य निश्चित करके लोगों को उनकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करने को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। निजी क्षेत्र में पण्य–व्यवस्था मुख्यतः नियामक है, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशासनिक आदेश नियामक हो सकता है। यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण प्रशासनिक आदेशों के अधीन करने का प्रयत्न किया जाएगा तो चोरबाजारी जैसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी तथा लोग अपने स्वातंत्र्य पर बंधन अनुभव करने लगेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विवरणमूलक तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक नीति नियामक होनी चाहिए। वास्तव में तो योजना की व्यूह नीति होनी चाहिए। उन अवस्थाओं का निर्माण करनेवाली वित्तीय, मौद्रिक एवं औद्योगिक नीतियों को अपनाना, जिनमें व्यक्ति के साहस को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिले तथा विनियोजन एवं वितरण बाज़ार–व्यवस्था के अंतर्गत ही वांछित दिशाओं में प्रवाहित हो। नियोजन, नीति–निर्धारण, नियमन, नियंत्रण और राष्ट्रीयकरण इनका क्रमावरोही रूप मेंप्रयोग करना चाहिए।

जनवरी, 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज

उद्देश्य– योजना के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए–

- राष्ट्र को सुरक्षा सक्षम बनाना।
- पूर्ण रोजगार।
- प्रत्येक कुटुंब की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसके स्तर को ऊंचा उठाना।
- आय और संपत्ति की विषमताओं में कमी करना।
- विकासमान अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ध्यान में रखते हुए भी राष्ट्र को मूलभूत उपभोग एवं उत्पादक वस्तुओं में आत्मनिर्भर बनाना।
- सभी क्षेत्रों और जनों का विकास।

वरीयताएं – यद्यपि कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवाएं, इन चारों का संतुलित विकास ही एक अच्छी अर्थव्यवस्था का लक्षण है, और हमें इन सबकी ओर ध्यान देना होगा, किंतु विकास को गति देने के लिए निम्नलिखित वरीयताओं का निर्धारण होना चाहिएकृ

1. सुरक्षा उद्योगों की स्थापना।
2. कृषि उत्पादन में वृद्धि।
3. जीवन की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए श्रम–प्रधान उद्योगों का विस्तार।
4. सार्वजनिक सेवाओं तथा मूलभूत उद्योगों की स्थापना।

मूल्य नीति

मूल्य नीति नियोजन का अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग है। मूल्य समाज के विभिन्न वर्गों की उपभोग–क्षमता के सूचक ही नहीं, अपितु वे वितरण और विनियोजन की दिशा भी प्रभावित करते हैं। अर्थनीति के आधुनिकीकरण में मूल्यों का कुछ अंशों में बढ़ना स्वाभाविक है, किंतु जब वे तेजी से बढ़ते अथवा गिरते हैं या विभिन्न कालों और क्षेत्रों के मूल्यों में भारी अंतर होता है तब उनसे जनजीवन तो संत्रस्त होता ही है, नियोजित विकास में भी भारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। यह अंतर उत्पादक याउपभोक्ता को लाभ नहीं पहुंचाता। इससे विनियोजन कृषि और उद्योगों की ओर प्रवाहित न होकर व्यापार और वितरण की ओर जाता है। सट्टे की प्रवृत्ति बढ़ती है। अतः मूल्यों का स्थिरीकरण अत्यंत आवश्यक है।

मूल्य नीति का उद्देश्य कच्चे और पक्के माल के मूल्य, वेतन और उजरत, ब्याज और लाभ के बीच सामंजस्य बनाए रखना तथा विनियोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। प्रशासकीय आदेशों के द्वारा मूल्यों को नियंत्रित करने के स्थान पर उन्हें वित्तीय, मौद्रिक, औद्योगिक आदि

आर्थिक नीतियों एवं नियमन के उपायों से प्रभावित करना वांछनीय होगा।

खाद्य एवं कृषि

न्यूनतम आवश्यकताओं में से खाद्य एक ऐसी आवश्यकता है, जिसके बिना प्राणिमात्र जीवित नहीं रह सकता। 'अन्न वै प्राणः' अर्थात् अन्न ही जीवन है। खाद्य के संबंध में पर निर्भरता राष्ट्रीय, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी भारत के लिए हानिकारक है। जिन देशों से हम अन्न प्राप्त करते रहे हैं, उनको निर्यात करने योग्य हमारे पास विशेष कुछ नहीं है। फलतः विदेशी ऋणों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इन ऋणों की अदायगी अथवा विभिन्न समझौतों के अंतर्गत मिश्रधन का विनियोग समस्यापूर्ण है। खाद्य में आत्मनिर्भरता उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता।

अन्न, फल, दुग्ध, मांस, मछली, अंडे आदि खाद्य के अंतर्गत आते हैं। किंतु खाद्य पूर्ति की कोई भी योजना जनता के दृष्टिकोण, उसके संस्कार तथा भावनाओं का विचार करके ही बनानी होगी। कृषि, दूध और उससे बनी चीजें ही हमारे आहार का मुख्य अंग हैं। हमें उनके उत्पादन पर ही सर्वाधिक बल देना होगा।

न्यूनतम आवश्यकताओं में से खाद्य एक ऐसी आवश्यकता है, जिसके बिना प्राणिमात्र जीवित नहीं रह सकता। 'अन्न वै प्राणः' अर्थात् अन्न ही जीवन है। खाद्य के संबंध में पर निर्भरता राष्ट्रीय, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी भारत के लिए हानिकारक है

जिस समाज में अधिकांश व्यक्ति खाद्योत्पादन में ही लगे रहें तथा खाद्योत्पादकों की क्रयशक्ति बहुत थोड़ी हो, वहां अर्थव्यवस्था के विविधीकरण तथा विकास की संभावना नहीं। भारत में आज 69.8 प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं तथा उनमें अधिकांश भूमिहीन या इतने छोटे किसान हैं कि वे कठिनाई से जीवन निर्वाह के लिए अन्न पैदा कर पाते हैं। उनके पास बाजार में बेचने के लिए अनाज नहीं होता। जब तक कृषि का विपणनीय अतिरेक नहीं बढ़ता, तब तक न तो कृषितर पेशों में लगे व्यक्तियों को खाद्य की सुविधा होगी और न किसान का जीवन स्तर ऊंचा होगा। जबरिया गल्ला वसूली, लेवी या मजबूरी में बिक्री की पद्धतियों से किसान से गल्ला लेने का तरीका ठीक नहीं। उपयुक्त तो यह होगा कि एक ओर तो किसान के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बेचने के लिए गल्ला हो और दूसरी ओर उसे उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग हो, जो कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इसके लिए खेती के उत्पादन में वृद्धि, खेती पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या में कमी, फ़सल का अच्छा दाम तथा कृषक के जीवन स्तर को ऊंचा करने की चाह, इन उद्देश्यों को लेकर ग्राम विकास कार्यक्रम अपनाने होंगे। भारत में भूमि की कमी होने के कारण हमें प्रति व्यक्ति के साथ प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन करना होगा। खेती, लाभप्रद मूल्य तथा ग्रामों का औद्योगीकरण हमारे कार्यक्रम की आधारशिला होने चाहिए।

कृषि विकास के लिए भूधृति संबंधी विद्यमान संस्थाओं को बदलना होगा, कृषि की पद्धति में प्राविधिक सुधार करने होंगे तथा साधनों को जुटाने एवं विपणन की व्यवस्था के लिए संस्थाएं बनानी होंगी। इस दृष्टि से एक समन्वित एवं सुनियोजित कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए। ग्राम के उद्योग–धंधों का भी इसके साथ विचार आवश्यक है।

खेती करने की पद्धति में सुधार

जहां तक खेती की पद्धति का संबंध है, भारत के किसान ने परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त पद्धतियों का विकास किया है। युगों से चली आई पद्धतियों को आज की उन प्रक्रियाओं के पक्ष में, जिन पर न तो पूरे–पूरे प्रयोग हुए हैं और न भारत की समसमान अवस्थाओं में उन प्रयोगों को किया गया है, एकाएक नहीं छोड़ देना चाहिए। भारत का किसान फसलों की अदल–बदलकर बुआई, हरी खाद का प्रयोग, मल–मूत्र की खाद का पकाकर उपयोग करना, भूक्षरण रोकने के लिए मेड़ बांधना तथा वृक्ष लगाना आदि विधियों को भली–भांति जानता है। उसने युगों से भूमि की उर्वरता को बनाए रखा है। हां, पिछले दिनों में विभिन्न कारणों से वह इस ज्ञान का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। उसके पूंजीगत साधनों को बढ़ाने तथा उसके मन में भूस्वामित्व के संबंध में निश्ंचितता पैदा करने की आवश्यकता है। नया प्रयोग और नया ज्ञान उसी अवस्था में संक्रमणशील रहता है, जब समसमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों का सफल अनुभव उसके पीछे हो। इस दृष्टि से गांवों में योग्य कृषकों को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए। सरकारी फार्मों के स्थान पर इन कृषकों के खेतों को ही मॉडल फार्म बनाना चाहिए।

उपज बढ़ाने तथा भूमि की उर्वरता टिकाए रखने के लिए खाद की आवश्यकता है। उर्वरक और खाद की मात्रा तथा क़िस्म मिट्टी, सिंचाई के साधन, फसल, उत्पादन की पद्धति आदि पर निर्भर है। प्रत्येक विकास खंड में एक परीक्षणशाला होनी चाहिए, जो इस हेतु आवश्यक जांच करके किसानों को उचित सलाह दे सके।

भारी ट्रैक्टर और मशीनों से खेती भारत के लिए अनुपयुक्त है। बंजर तोड़ने में उनका अवश्य उपयोग हो सकता है। अच्छे औजार, बैल, खाद, उन्नत बीज, ऋण तथा विपणन के लिए साधन, सहकारी समितियों का गठन उपयोगी होगा। ■

श्रद्धांजलि

"लता दीदी को कोटिशः नमन!"

भारत रत्न और सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। यहां कोरोना और उसके बाद निमोनिया पीड़ित हो गईं। करीब 29 दिन तक हॉस्पिटल में इलाज चला। लताजी के निधन पर दो दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित रहा। लताजी के निधन से हर कोई दुखी है। लताजी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। नेताओं से लेकर अभिनेताओं ने भी दुख जताया और श्रद्धांजलि दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनकी अन्तिम यात्रा में शामिल हुए, उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर साम्राज्ञी, परम श्रद्धेय लता मंगेशकर जी के निधन से अन्तर्मन दुख, पीड़ा, शोक से व्यथित है। देश ही नहीं, समूचे विश्व ने एक ऐसी स्वर साधिका को खो दिया, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से जीवन में आनंद घोलने वाले असंख्य गीत दिए। लता दीदी का तपस्वी जीवन स्वर साधना का अप्रतिम अध्याय है। गीत–संगीत के प्रति समर्पण से परिष्कृत आपका व्यक्तित्व शालीनता, सौम्यता व आत्मीयता की त्रिवेणी रहा, जो कला साधकों को अनंतकाल तक प्रेरित करता रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। अपनी सुमधुर अमर आवाज से लता दीदी सदैव हम सभी के बीच रहेंगी।

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री व पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री धर्मेन्द्र प्रधान, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, केन्द्रीय मंत्री व पार्टी के चुनाव सहप्रभारी श्री अनुराग ठाकुर, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल सहित पार्टी पदाधिकारियों ने श्रद्धेय लता मंगेशकर जी के निधन पर शोक प्रकट किया।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारत रत्न श्रद्धेय लता मंगेशकर जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आज देश के लिए बहुत दुखःद समाचार आया हैं। स्वर कोकिला भारत रत्न श्रद्धेय लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। उनके जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार आता है। आज संगीत ही नहीं बल्कि समाज व राष्ट्र की अपूरणीय क्षति हैं। लता जी भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति थी। दो मिनट का मौन रख सबने श्रद्धांजलि अर्पित किया।

संवाद

फिर सरकार
300 पार

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2021-23
संकल्प से सिद्धि, फरवरी प्रथम अंक 2022 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 11–13 (प्रथम पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी